सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 308 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 22 अगस्त 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

48 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नेशनल टीचर्स अवॉर्ड 2026 का ऐलान किया है। देशभर से 48 शिक्षकों को चुना गया है। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला टीचर हैं। इनमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आदर्श जनजातीय स्कूल और पीएम श्री स्कूलों समेत कई संस्थानों के शिक्षक चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से सुनीता यादव का चयन हुआ है। सर्वाधिक तीन शिक्षक उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को शिक्षकों को ये पुरस्कार देंगी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों को बस ने रौंदा, 5 की मौत

बेतिया। लौरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार बस सड़क किनारे चल रहे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में जा घुसी। वहां मौजूद लोगों को रौंद दिया। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हो गए जबकि 5 की मौत हो गई। मृतकों की पहचान लौरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा निवासी बहादुर महतो, संजय कुमार, भोला दुबे, देवेंद्र दुबे और छांगुर राम के रूप में हुई है। देवेंद्र दुबे के बेटे की छठी थी, उसी कार्यक्रम में डांस हो रहा था।

थलपति ने दिया सवा लाख सोने की अंगूठियों का आर्डर

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए 'थाई मामन स्वर्ण अंगूठी योजना' के तहत सोने की अंगूठियां खरीदने के लिए दो आभूषण कंपनियों को कार्यादेश जारी किया है। सरकार यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री सी. एन. अन्नादुरई की जयंती के अवसर पर 15 सितंबर को शुरू करने जा रही है। सरकार ने शुक्रवार देर रात बताया कि तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम (टीएनएमएससी) ने जून से सितंबर तक के लाभार्थियों के लिए आवश्यक सोने की 1,28,499 अंगूठियों की आपूर्ति के लिए जॉय अलुक्कास और कल्याण ज्वैलर्स को 70:30 के अनुपात में कार्यादेश जारी किए हैं।

गूगल मैप के चक्कर में खाई में उतर गई स्टूडेंट्स की बस

खरगोन। महाराष्ट्र के कोपरगांव स्थित संजीवनी यूनिवर्सिटी के बी.टेक छात्रों को लेकर जा रही बस घाट उतरते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी सुरक्षा रैलिंग से टकरा गई। बस का एक हिस्सा करीब 1000 फीट गहरी खाई की ओर लटक गया। मंडलेश्वर एसडीओपी श्वेता शुक्ला ने बताया कि बस में कुल 53 लोग सवार थे। छात्रों ने महेश्वर में नर्मदा दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम बनाया था। इसी दौरान ड्राइवर ने गूगल मैप पर दिख रहे शॉर्टकट को अपनाया और बस जाम गेट की ओर आ गई। दरअसल, मैप से यह पता नहीं लगा कि जाम गेट का यह रास्ता बड़े और भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है।

हिमाचल में बनी 83 समेत देश भर में निर्मित 239 दवाइयों के सैम्पल फेल, वापस मंगाई जाएंगी

शिमला (ए.)। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएसओ) की ओर से करवाई 40 सैंपलों की जांच में हिमाचल की 12 दवाओं के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए। राज्य प्रयोगशालाओं में 199 सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें 71 सैंपल हिमाचल में बनी दवाओं के शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बनी 83 दवाओं समेत देशभर में 239 दवाइयों के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं।

जुलाई के ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हिमाचल के सोलन जिले में 56, सिरमौर में 9, ऊना जिले में पांच और कांगड़ा जिले में तीन दवा कंपनियों के सैंपल जांच में फेल हुए हैं।

बद्दी की एक कंपनी के पांच सैंपल एक साथ फेल हुए हैं। ये पांच सैंपल आयरन की कमी के लिए प्रयोग होने वाली दवा के हैं। जांच में झाड़माजरी की लाइव वेव कंपनी के विटामिन डी, बद्दी सेमसन लेबोट्री के दर्द व

सूजन, बद्दी की हिंदुस्तान पोलीपेव कंपनी के शरीर में पानी की कमी की दवा के दो सैंपल फेल हुए हैं। सुबाथू की जेएम लेबोरेट्री कंपनी, बद्दी की मर्टिन एंड क्राऊन कंपनी की एसिड, बरोटीवाला की फोरगो कंपनी की सूखी खांसी, कांगड़ा की मेडीरोज कंपनी की बुखार, एक्मे कंपनी की फोलिक एसिड, बद्दी की सेरवेदिक कंपनी की एनीमिया, विग्स बायोटेक कंपनी की नसों की कमजोरी की दवा के सैंपल फेल हुए हैं। इसके अलावा कई अन्य दवाओं के सैंपल भी मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं।

वापस मंगवाया जाएगा स्टॉक

राज्य ड्रग नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने बताया कि सैंपल फेल होने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फेल होने वाली दवा को बाजार से वापस मंगाने को कहा जाएगा।

इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय पेपर लीक, वाट्सऐप चैट के आधार पर दुर्ग के प्रोफेसर समेत छह गिरफ्तार

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जांच में तेजी, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर जीरो टॉलरेंस की नीति

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। पेपर लीक पर देश भर में चल रहे हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस ने दो दिन के भीतर पीपर लीक के आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस शाम तक मामले का खुलासा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने वाट्सऐप चैट के आधार पर दुर्ग के एक निजी महाविद्यालय के प्राध्यापक समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कीट विज्ञान परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। जांच में पेपर लीक का कनेक्शन दुर्ग के एक निजी कॉलेज से सामने आया है।

पुलिस ने मामले में एक प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान कुछ छात्रों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस आज पूरे मामले का खुलासा करेगी।

20 अगस्त को आईजीकेवी की कीट विज्ञान की परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से करीब दो घंटे पहले प्रश्नपत्र वॉट्सऐप के जरिए छात्रों तक पहुंच गया था।

पेपर वायरल होने की जानकारी सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा स्थगित कर दी थी। मामले की शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने जांच के दौरान रायपुर के अलावा दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव और बिलासपुर में दबिश दी। तकनीकी जांच, मोबाइल और वॉट्सऐप चैट के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों तक पहुंच बनाई।

इसके बाद प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को आशंका है कि प्रश्नपत्र पहले दुर्ग के निजी कॉलेज से बाहर निकला और इसके बाद वॉट्सऐप के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया।

जांच में कुछ छात्रों के भी इस नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रश्नपत्र किस स्तर पर लीक हुआ और इसे किन-किन लोगों तक भेजा गया। मामले में अब तक 16 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कवर्धा के दो छात्रों से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मोबाइल चैट और तकनीकी साक्ष्यों की जांच के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। पेपर लीक के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और सख्त जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल चैट की जांच के आधार पर कार्रवाई तेज की। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

सीमेंट फैक्ट्री के पावर प्लांट में धमाका, 3 अफसरों की मौत

रामगढ़ (झारखंड) (ए.)। रामगढ़ के बरकाकाना में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में काम के दौरान अचानक टरबाइन ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियर्स की झुलसने से मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी (50), बोकारो के जगेश्वर बिहार के विनीत महतो (25) और गढ़वा निवासी अभिषेक पांडेय (24) के रूप में हुई है। घायल मजदूर तरुण रजवार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।

ब्लास्ट और आग लगने की सूचना मिलते ही फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद रामगढ़ से चार-पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद फैक्ट्री के पावर

प्लांट में लगी आग पर काबू पाया।

मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण फैक्ट्री गेट जाम करने की तैयारी में हैं। तीनों शव वापस फैक्ट्री के पास लाया जा रहा है। घटना को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

फैक्ट्री के पावर प्लांट यूनिट के इन्चार्ज अनुराग त्रिपाठी ने हादसे के लिए प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। अनुराग ने आरोप लगाया कि प्लांट में तापमान बढ़ने और ओवरहीटिंग के कारण यह हादसा हुआ। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट से एसी लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

प्रार्थना से दुःख-दर्द और बीमारी ठीक करने का दावा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भनपुरी इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर लालच देने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित को प्रार्थना के बल पर रोगमुक्त करने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कथित रूप से हिन्दू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें भी कहीं।

गांधी चौक न्यू आनंद नगर निवासी 32 दुकानदार तरेन्द्र कुमार वर्मा ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर तीन महिलाओं के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं। तरेन्द्र ने बताया कि सुषमा कोशिक, लक्ष्मी निषाद

और सुरेखा रंगारे उसकी परिचित हैं और उसकी मोबाइल दुकान पर आती-जाती हैं। तीनों ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं और उसे ईसाई धर्म अपनाने, यीशु की प्रार्थना करने के लिए कहा। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि महिलाओं ने प्रार्थना करने से दुख-दर्द और बीमारी दूर होने की बात कही।

तरेन्द्र के मुताबिक, सुषमा ने उसे अपने घर में प्रार्थना सभा होने की जानकारी दी थी और वहां आने के लिए कहा था। 21 अगस्त को दोपहर करीब 2:30 बजे वह सुषमा के घर पहुंचा। सुषमा उसे अंदर ले गई, जहां करीब 20-25 लोग प्रार्थना कर रहे थे। वहां मौजूद सुषमा, लक्ष्मी और सुरेखा ने उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा और प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया। उसने धर्म बदलने से इनकार कर वहां से बाहर निकलने की बात कही।

जेन-जी से जुड़ने भाजपा की टीम, ये हैं सदस्य

नई दिल्ली (ए.)। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को पार्टी की 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम के साथ पहली बैठक की। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, बूथ और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

वहीं जेन-जी से जुड़ने के लिए टीम बनाई गई है। इसमें नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति

ईरानी और विनोद तावड़े, गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी समेत कई नेता शामिल हैं। पार्टी कार्यक्रम के जरिए युवाओं की सोच, जरूरतों और समस्याओं को समझने और उनसे सीधे संवाद करने की कोशिश करेगी।

नवीन ने 17 अगस्त को 65 सदस्यीय नई टीम का ऐलान किया था। इसमें 51 नए चेहरे शामिल हैं। टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव हैं। नई टीम में अगले साल चुनाव वाले 4 राज्यों के 18 नेताओं को भी जगह दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश से 8, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4 और पंजाब से 2 नेता शामिल हैं।

रिश्वतखोरों की पोल खोलने वाली वेबसाइट 48 घंटे में हुई बंद, 50 लाख रिक्वेस्ट मिले

नई दिल्ली (ए.)। रिश्वतखोरों की पोल खोलने वाली एक क्राउड फंडेड एंटी ब्राइबरी वेबसाइट अचानक बंद हो गई है। पोर्टल के लॉन्च होने के महज 48 घंटे के अंदर ही इसे 50 लाख रिक्वेस्ट और 2 लाख यूजर्स मिल गए थे। इसे दिल्ली के 20 साल के बी.टेक स्टूडेंट आर्यन निषाद ने बनाया था। इसमें रिश्वत मांगने वालों की गुमनाम रिपोर्ट की जा सकती थीं।

खास बात ये है कि इस पोर्टल पर 17 अगस्त तक, 253 शहरों से रिपोर्ट आ चुकी थीं। इनमें पुलिस, आरटीओ, रेवेन्यू और जमीन के रिकॉर्ड वाले ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ शिकायतें शामिल थीं।

आर्यन ने वेबसाइट बंद होने की वजह ज्यादा ट्रैफिक, डेटा सिक्योरिटी, स्पैम, डुप्लीकेट एंट्री और गलत इस्तेमाल बताई गई। टीम की ओर से कहा गया कि हमने इतने बड़े पैमाने पर मिल रही सूचनाओं को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था। उन्होंने माना कि इतने बड़े स्तर पर इसे संभालने के लिए वे सही कस्टोडियन नहीं थे। अपने विदाई नोट में उन्होंने कहा कि इसे बंद करना हमारा फैसला था। इसका मकसद एक संदेश देना था, न कि किसी पर उंगली उठाना जो कि पूरा हो चुका है।

वाराणसी के सभी घाट डूबे, छतों पर आरती-अंतिम संस्कार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखनऊ-बाराबंकी समेत 5 शहरों में शनिवार सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है। वाराणसी में सभी 84 घाट डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट की छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी छत पर कराई जा रही है। महीना खत्म होने से पहले अगस्त में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सफदरजंग मौसम केंद्र में 1 से 21 अगस्त के बीच 235.3 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि अगस्त की सामान्य बारिश 233.1 मिमी है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में वीकेंड पर भी बारिश जारी रह सकती है।

बीएसपी से लोहा चोरी का मामला

गृहमंत्री ने इस्पात मंत्रालय को भेजी विधायक की शिकायत

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा की गई बीएसपी से लोहा चोरी संबंधी शिकायत को इस्पात मंत्रालय को भेज दिया है। इसके साथ ही विधायक रिकेश सेन ने दावा किया है कि मामला केन्द्र सरकार तक पहुंच गया है और जल्द ही बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी। सीबीआई जांच के साथ ही कई सफेदपोशों की गिरफ्तारी भी होगी।

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने 20 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। गृह मंत्री की ओर से विधायक को जवाब

मिला है। इसमें बताया गया है कि उनका पत्र प्राप्त हुआ था। मामला इस्पात मंत्रालय से संबंधित होने के कारण उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया है।

अमित शाह के जवाब के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई इस्पात मंत्रालय के स्तर पर होनी है। हालांकि, गृहमंत्री के जवाब में सीबीआई जांच शुरू करने या मामले को सीबीआई को सौंपने का कोई जिक्र नहीं है। वहीं, विधायक रिकेश सेन ने कहा है कि मामला केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है और जल्द ही सीबीआई जांच शुरू होगी। उन्होंने दावा किया कि जांच में लोहा चोरी से जुड़े कई बड़े सफेदपोश लोगों की भूमिका सामने आएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। विधायक सेन ने कहा कि इस संबंध में सकारात्मक चर्चा भी हुई है। जल्द ही लोहा चोरी मामले में सीबीआई की एंट्री होगी। निष्पक्ष जांच के बाद इस मामले में कई बड़े सफेदपोश और समाजसेवी जेल जाएंगे।

क्या है मामला?

इस पूरे मामले की शुरुआत 26 मई को हुई थी। पुलिस ने अकलोरडीह और हथखोज स्थित गोदामों में कार्रवाई कर करीब 250 टन बीएसपी का लौह स्क्रैप बरामद किया था। स्क्रैप को फ्लू डस्ट की आड़ में प्लांट से बाहर निकाला जा रहा था। वाहनों में ऊपर फ्लू डस्ट और उसके नीचे लोहे की प्लेट, बीम और कटिंग मटेरियल रखा जाता था।

राहुल के कार्यक्रम से पहले छात्र संघों में झड़प

पुणे। सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में शुक्रवार रात को एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यह विवाद राहुल गांधी के शनिवार को होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले हुआ। घटना के बाद हॉस्टल में पुलिस तैनात की गई। एबीवीपी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता छात्राओं पर राहुल के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का दबाव डाल रहे थे। वहीं, एनएसयूआई ने दावा किया कि कार्यक्रम के समर्थन में बोलने वाली 2 छात्राओं को एबीवीपी सदस्यों ने हॉस्टल में रोककर धमकाया। पुलिस ने 6 नामजद लोगों और करीब 50-60 एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है।

संपादकीय

मिठास की खटास

इथेनॉल के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में चीनी का यथार्थ

हाल के दिनों में बाजारों में चीनी की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया है। वहीं चीनी की कालाबाजारी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने इसकी बिक्री का नियमन भी किया है। साथ ही सरकार ने बिना टैक्स दस लाख टन कच्ची चीनी के आयात की इजाजत देने का भी फैसला किया है। लेकिन सरकार का यह फैसला शायद ही बढ़ती कीमतों का जवाब हो। निस्संदेह, यह परिदृश्य सरकार के लिये उसकी महत्वाकांक्षी इथेनॉल नीति की असलियत को समझने का एक अवसर भी है। पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल की बिक्री व्यवस्था लागू करने का जश्न मनाने के दो साल से भी कम समय में सरकार अब दो परस्पर विरोधी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। पहला, देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिये कच्चे तेल के आयात को कम करना और दूसरा उपभोक्ताओं के लिये सस्ती चीनी उपलब्ध कराना। निस्संदेह,यह घटनाक्रम एक नीतिगत दुविधा को तो दर्शाता है कि जब एक ही फसल का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ और ईंधन, दोनों के लिये किया जाता है, तो किसी एक लक्ष्य को दूसरे से अलग रखकर पूरा नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, ऐसे वक्त में जब खाड़ी संकट के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों का संकट व्याप्त रहा, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ने देश के नागरिकों व सरकार को बड़ी राहत दी है। इसमें दो राय नहीं कि निर्धारित समय सीमा से पहले ही बीस फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य हासिल करके, भारत ने आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कुछ कम जरूर किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार की इस अभिनव पहल से जहां एक ओर चीनी मिलों को सहारा मिला है,वहीं गन्ना किसानों के लिये कमाई का एक अतिरिक्त जरिया भी बना है। निश्चित रूप से उस देश के लिये यह एक उपलब्धि ही कही जा सकती है जो अपनी जरूरतों के लिये 85 फीसदी कच्चे तेल का आयात करता रहा है। वह भी अपने देश में उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों के जरिये।

> “ पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल की बिक्री व्यवस्था लागू करने का जश्न मनाने के दो साल से भी कम समय में सरकार अब दो परस्पर विरोधी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। पहला, देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिये कच्चे तेल के आयात को कम करना और दूसरा उपभोक्ताओं के लिये सस्ती चीनी उपलब्ध कराना। निस्संदेह,यह घटनाक्रम एक नीतिगत दुविधा को तो दर्शाता है कि जब एक ही फसल का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ और ईंधन, दोनों के लिये किया जाता है, तो किसी एक लक्ष्य को दूसरे से अलग रखकर पूरा नहीं किया जा सकता है।

इसके बावजूद राजग सरकार की इस रचनात्मक पहल की कुछ बुनियादी खामियां भी हमारे सामने उजागर हुई हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि गन्ना भारत में सबसे ज्यादा पानी की खपत करने वाली फसलों में से एक है। वहीं दूसरी ओर इथेनॉल के उत्पादन के लिये गन्ने का इस्तेमाल ऐसे समय में शुरू हुआ है जब देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में शुमार महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैदावार खराब मौसम और गन्ने की फसल पर लगी बीमारियों के चलते कमजोर रही है। यह भी एक वजह है कि गन्ना आपूर्ति में आई कमी के चलते भी हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई है। जिसके चलते सरकार को चीनी का निर्यात रोकना पड़ा है। इतना ही नहीं, सरकार को आसन्न त्योहारी मौसम को देखते हुए अब कच्ची चीनी के आयात को अनुमति देनी पड़ी है। निस्संदेह, इन परिस्थितियों के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता कि देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग विफल हो गया है। बल्कि यह समझने की जरूरत है कि देश की कृषि संबंधी वास्तविकताओं और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की खाद्य जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि देश में एक लचीली जैव ईंधन रणनीति को तार्किक बनाया जाए। जिसे फसलों की स्थितियों और घरेलू खाद्य जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके। निस्संदेह, फसलों के अवशेष और कृषि अपशिष्ट से निर्मित होने वाले इथेनॉल में अधिक निवेश करने से ही गन्ने पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही जलवायु लक्ष्यों को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। भारत द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के लक्ष्य के रूप में कामयाबी एक सराहनीय उपलब्धि कही जा सकती है। निस्संदेह यह उपलब्धि खाद्य मुद्रास्फीति या जल के अंधाधुंध दोहन की कीमत पर नहीं हासिल की जा सकती। सही मायने में सबसे अच्छी नीति वही मानी जाएगी, जो ईंधन के टैंक और रसोई के भंडार पर्याप्त मात्रा में भरा रख सके।

कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर ब्रिटेन का निकलना!

श्याम भाटिया

असली सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश यह समझते हैं कि उनके आखिरी दिनों में लिए गए फैसलों का असर आज भी करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को आकार दे रहा है। दिल्ली-इस्लामाबाद की नवीनतम घटनाओं से तो लगता है कि इतिहास अभी भी अतीत नहीं बना, वहीं का वहीं खड़ा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच की 'जैसे को तैसा' जवाब देने की प्रवृत्ति और अविश्वास के मिलेजुले भाव से देखना दिलचस्प है। बुधवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर का दौरा किया और जम्मू-कश्मीर को 'भारत का अहम हिस्सा' बताया। पाकिस्तान ने तुरंत इसका विरोध किया। इसके बाद राजनयिक स्तर पर 'जैसे को तैसा' वाला दौर शुरू हुआ : पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे सुरक्षा बैरियर हटवा दिए; तो जवाबी प्रतिक्रिया में भारत ने भी नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर ठीक वही किया।

भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उनकी उम्र लगभग 80 साल हो चुकी है। लेकिन वे अभी भी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो दिवंगत माता-पिता की विरासत के लिए झगड़ रहे बच्चे हों। ज़ाहिर है, यहां 'दिवंगत माता-पिता' से अभिप्राय ब्रिटिश साम्राज्य से है। इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है: 1947 में पीछे छोड़ दिए गए 'ताज के रत्न' (भारत) को ब्रिटेन किस नज़रिए से देखता है? क्या ब्रिटेन वाकई अतीत को भूलकर आगे बढ़ गया है? मुझे शक है कि इसका जवाब उससे कहीं ज़्यादा जटिल है, जितना ब्रिटिश या उनकी पूर्व प्रजा स्वीकार करना चाहेगी। भारत से ब्रिटेन की वापसी असाधारण रूप से जल्दबाज़ी में हुई थी। फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली की सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक खत्म हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर आए और उन्होंने इस समय-सीमा को सरका कर पहले कर दिया। अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। नए देशों की सीमाओं की घोषणा सिर्फ दो दिन बाद की गई। लाखों लोगों को अचानक पता चला कि वे एक ब्रिटिश वकील, सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गई रेखा के गलत तरफ रह रहे हैं, जो इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे।

इसके नतीजे बहुत भयानक रहे—बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन, सांप्रदायिक नरसंहार और कड़वाहट की ऐसी विरासत, जो पीढ़ियों तक बनी रही। और फिर कश्मीर का मुद्दा था। यह महज़ ज़मीन का कोई टुकड़ा भर नहीं था, जिसे एक नया देश आसानी से दूसरे देश को सौंप दे। जम्मू-कश्मीर एक रियासत थी, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह ने काफी हील-हुज्जत के बाद अक्तूबर 1947 में भारत में विलय के दस्तावेज़ (इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किए थे। इसे गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया, जो आज़ादी के बाद भी भारत के गवर्नर-जनरल बने रहे। संलग्न पत्र में उन्होंने लिखा था कि जब कानून-व्यवस्था बहाल हो जाएगी, तो विलय का सवाल लोगों की राय से तय किया जाना चाहिए। वह अनसुलझा इतिहास भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में सबसे बड़ा ज़ख्म बन गया। तीन युद्ध हुए, सशस्त्र विद्रोह, आतंकवाद, सैन्य टकराव और न जाने कितने ही कूटनीतिक संकट आए।

आज 2026 में, हम देख रहे हैं कि परमाणु हथियार संपन्न दो देश एक-दूसरे के राजनयिक मिशनों के बाहर सुरक्षा इंतज़ामों को लेकर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि एक अमेरिकी राजदूत ने कश्मीर के बारे में कुछ ऐसा कहा जो पाकिस्तान को नागवार गुजरा। इन सबके लिए ब्रिटेन को दोष देना आसान होगा। लेकिन यह करना कुछ ज़्यादा ही आसान होगा। भारत और पाकिस्तान के पास परिपक्व होने के लिए लगभग आठ दशक थे। उनके नेताओं ने सुलह की बजाय बार-बार राष्ट्रवाद को चुना। दोनों देशों ने घरेलू राजनीतिक मकसदों के लिए कश्मीर का इस्तेमाल किया। दोनों ने बंटवारे और खुद को पीड़ित दिखाने के आधार पर मज़बूत प्रचार कथानक गढ़े हैं। सन 1947 के बाद से दिल्ली या इस्लामाबाद में लिए गए हर फैसले के लिए ब्रिटेन को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर, ब्रिटेन भी इतिहास से पूरी तरह बच नहीं सकता।

नि:संदेह, उसने ऐसे राजनीतिक हालात पैदा किए जिनमें बंटवारा हुआ। इसने तय किया कि मूल समयसीमा से पहले ही यहां से चले जाना है। उसने पंजाब और बंगाल के बंटवारे की निगरानी की। सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया में ब्रिटिश अधिकारी गहराई तक शामिल थे। ब्रिटिश राष्ट्रीय संग्रहालय के रिकॉर्ड से स्थापित होता है कि ब्रिटिश अधिकारियों के पास यह तय करने के लिए सिर्फ नौ हफ़्ते थे कि ब्रिटिश भारत का बंटवारा कैसे किया जाए। और फिर ब्रिटेन के सूत्रधार अपने देश लौट गए।

शायद कहानी का सबसे असाधारण हिस्सा यही है। ब्रिटिश साम्राज्य नक्शे से गायब हो गया, लेकिन उसकी सीमाएं नहीं गईं। उसके बनाए संस्थान पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उसकी अंग्रेज़ी भाषा नए रसूखदार वर्ग की गर्व योग्य बोली बन गई। उसकी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। उसकी सेना का ढांचा, प्रशासनिक परंपराएं और कानूनी नियम बने रहे। और उसके जाने के दौरान बने ज़ख्म भी बने रहे। तथापि, ब्रिटेन खुद काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। आज का ब्रिटेन बिल्कुल अलग सवालों में उलझा हुआ है: ब्रेक्सिट, आप्रवासन, एनएचएस, जीवन-यापन की बढ़ती लागत, सुधार, पारंपरिक राजनीतिक दलों का पतन और दुनिया में उसकी अनिश्चित स्थिति।

वहीं, भारत और पाकिस्तान इस बीच अभी भी उस इलाके को लेकर झगड़ रहे हैं, जिसका आधुनिक राजनीतिक भविष्य उपमहाद्वीप में ब्रिटेन के आखिरी महीनों के दौरान तय हुआ था। इस पूरे मामले में कुछ-कुछ शेक्सपियर के नाटकों जैसी बात है। ब्रिटेन ने मंच छोड़ दिया, कलाकार बदल गए, वेशभूषा बदल गई, दर्शक बदल गए, लेकिन झगड़ा जारी रहा।

शायद इस बात की असली परीक्षा यह नहीं है कि क्या ब्रिटेन अपने साम्राज्य वाले दिनों को छोड़कर आगे बढ़ चुका है और क्या ब्रिटेन के लोग अब भी 'राज' के पुराने वैभव की खुमारी में खोए रहते हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश यह समझते हैं कि उनके आखिरी दिनों में लिए गए फैसलों का असर आज भी करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को आकार दे रहा है। दिल्ली-इस्लामाबाद की नवीनतम घटनाओं से तो लगता है कि इतिहास अभी भी अतीत नहीं बना, वहीं का वहीं खड़ा है। 'ताज का रत्न' अब दो मज़बूत स्वतंत्र देश बन चुके हैं, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न हैं, और भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। दोनों देशों ने अपना-अपना इतिहास, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपनी-अपनी पहचान विकसित कर ली है। वे अब ब्रिटेन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन न तो ब्रिटेन और न ही दक्षिण एशिया के ये देश यह दिखावा कर सकते हैं कि जिस तरीके से ब्रिटेन यहाँ से गया, उससे बाद की घटनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। अस्सी साल बाद, शायद अब समय आ गया है कि तीनों देश उस असहज सच को स्वीकार करें।

ब्रिटिश राज 1947 में भारत से चला गया, लेकिन वह गया कैसे, इसका इतिहास कभी भारत से पूरी तरह नहीं गया।

लेखक लंदन स्थित वरिष्ठ पत्रकार हैं।

संघर्षों की तपिश में तपे निर्भीक तुकाराम

अरूण नैथानी

तुकाराम का मानना है कि यदि कोई जनसाधारण के उत्थान, विकास तथा नैतिक जीवन मूल्यों के साथ प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं तो स्वागत है। लेकिन यदि अपना भला करना मकसद है तो आईएएस अधिकारी न बनें।

व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व तंत्र की काहिली के खिलाफ मुखर रूप से खड़े होने वाले महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के बदलावकारी साहसिक कदमों की पूरे देश में चर्चा होती है। व्यवस्था को जस का तस बनाए रखने वाले राजनेता, धनाढ्य लोग और बाहुबली सदा उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस लड़ाई में कभी वे जीतते हैं तो कभी हारते हैं, मगर वे बार-बार होने वाले तबादलों के बावजूद, इसकी फिक्र किए बिना अपने काम में लगे रहते हैं। वे इसे व्यवस्था में बदलाव लाने का एक अवसर मानते हैं।

फिलहाल देशभर में उनकी चर्चा महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए आयुक्त बनने के बाद उनके उठाए कदमों को लेकर हो रही है। उन्होंने एनालॉग पनीर और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए हैं, उसका असर दूसरे राज्यों में सरकारों की एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्रवाई के रूप में सामने आया है। यहां तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टारों को सुगंधित पान-मसाले के विज्ञापन करने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने भी उनके प्रयासों को सराहा है। बहरहाल, रासायनिक पदार्थों वाले खाद्य पदार्थों, मिलावटी व नियम-विरुद्ध कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल करने वाले उत्पादकों-कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जनता की वाहवाही मिली है।

यह हमारी व्यवस्था की विडंबना है कि जब भी कोई अधिकारी व्यवस्था की काहिली तोड़ने की कोशिश करता है, तो राजनेता ही नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी व कर्मचारी तक उसके खिलाफ हो जाते हैं। तुकाराम जब नवी मुंबई नगर निगम आयुक्त बने तो भ्रष्टाचार व अव्यवस्था दूर करने के उनके अभियान के बाद उनके खिलाफ सत्तारूढ़ दल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया। लेकिन लोगों ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किए।

तुकाराम मुंढे हमेशा चाहते हैं कि कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आना चाहिए। नागपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहते हुए उन्होंने न केवल शिक्षकों की समय पर उपस्थिति अनिवार्य की, बल्कि ड्रेस कोड भी क्रियान्वित किया। स्पष्ट निर्देश थे कि निर्धारित समय के बाद लेट आने वाले शिक्षकों के लिए स्कूल का गेट बंद किया जाए। शिक्षकों ने उनका विरोध किया लेकिन परिषद को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। अब जब उन्होंने एफडीए में सख्ती दिखाई तो कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें दो शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। उन्हें सार्वजनिक अवकाश, शनिवार व रविवार को भी काम पर बुलाया जा रहा है। वहीं मुंढे का कहना है कि शिफ्ट व्यवस्था पहले से लागू थी। निर्धारित समय में यदि काम न हो तो व्यवस्था सुधार के लिए समय तो देना पड़ेगा।

दरअसल, तुकाराम चाहते हैं कि जनहित के काम समय पर हों। वे तुरंत-फुरंत एक्शन से व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। लेकिन बदलाव लाने के प्रयासों में राजनेताओं और कर्मचारी संगठनों से उनका टकराव हो जाता है। एक बार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहते हुए जब उन्होंने एक ग्राम सेवक यूनियन के नेता को निलंबित किया तो नेता ने उन पर पेपरवेट फेंका। इसी तरह पुणे की सरकारी परिवहन कंपनी के 600 से अधिक कर्मचारियों को जब कारण बताओ नोटिस दिया तो उनका काफी विरोध हुआ। फिर एक साल के भीतर उनका तबादला कर दिया गया। आलोचक मानते हैं कि वे काम तो बहुत तेजी से करते हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया जाता। फलत: बदलाव की कोशिश में टकराव होता है। वहीं समर्थकों का कहना है कि उनके फैसले जनभावना के बजाय कानून पर आधारित होते हैं। वे चाहते हैं कि हर काम कायदे-कानून से हो। निस्संदेह, तुकाराम एक ईमानदार अधिकारी हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कभी नहीं लगे। लेकिन कहीं न कहीं वे अपने वरिष्ठों व मातहतों से तालमेल बनाने में चूक जाते हैं।

महाराष्ट्र के बीड के ताडसोन्ना गांव से आने वाले मुंढे एक विपन्न किसान परिवार से आते हैं। वे बेहद मुश्किल हालातों से जूझते हुए आईएएस बनने के मुकाम तक पहुंचे। विषम हालातों तथा खेती-किसानी के संकट से उनका परिवार तंगी में रहा। परिवार के आर्थिक संकट के बीच संघर्षों ने उन्हें तपाया और मेहनकश बनाया। यहां तक कि साप्ताहिक पैठ में वे सिर पर टोकरी रखकर सब्जी बेचने तक गए। पढ़ाई के साथ खेतों में पिता के साथ हाथ भी बंटाया। यहां तक कि खेतों में हल भी चलाया। वे इतने संवेदनशील और मदद करने में विश्वास रखते थे कि पोलियोग्रस्त बड़े भाई को कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे। बकायदा उनकी खूब सेवा करते थे। परिवार में बड़े भाई अशोक मुंढे के अधिकारी बनने के बाद उनके दिमाग में आईएएस अधिकारी बनने का विचार सशक्त हुआ। बाद में पिता की इच्छा के विरुद्ध वे पढ़ने के लिए बड़े भाई के पास औरंगाबाद चले गए।

तुकाराम पढ़ने-लिखने में जुनूनी थे। उन्होंने संस्थागत पढ़ाई पूरी करने के बाद महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की। यहां तक कि नीट परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उन्हें फेलोशिप भी मिली। साल 2005 में यूपीएससी परीक्षा पास करके वे आईएएस अधिकारी बने। उनकी प्रतिभा व मेहनत का पता इस बात से चलता है कि पूरे देश में आईएएस में उनकी 20वीं रैंक थी। तुकाराम का स्पष्ट मानना है कि यदि आप जनसाधारण के उत्थान, विकास तथा नैतिक जीवन मूल्यों के साथ प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं तो स्वागत है। लेकिन यदि अपना व परिवार का भला करना मकसद है तो आईएएस अधिकारी न बनें।

अनुशासन के लिए बेंत शिक्षा की आत्मा पर चोट

डॉ. पुनित अरोरा

यदि विद्यालय बच्चे को भयमुक्त वातावरण नहीं दे सकता, तो शिक्षा का अधिकार अधूरा है। और यदि अनुशासन के नाम पर बेंत उठती है, तो चोट केवल बच्चे को नहीं लगती—चोट शिक्षा व्यवस्था की आत्मा और मानवाधिकारों की बुनियाद पर लगती है।

तमिलनाडु के तेनकासी जिले में कक्षा 10 की दस छात्राओं को एक शिक्षिका द्वारा कथित रूप से बेंत से पीटे जाने की घटना को केवल विद्यालय में अनुशासन की एक घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह घटना हमारे शिक्षा तंत्र के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती है—क्या विद्यालय केवल पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान हैं, या फिर वे ऐसे सुरक्षित और गरिमामय स्थान भी हैं, जहां बच्चे बिना भय के सीख सकें, अपनी बात रख सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास पैदा करना है। जिस हाथ में बच्चों को दिशा देने के लिए किताब और कलम होनी चाहिए, यदि उसी हाथ में बेंत आ जाए, तो चोट केवल शरीर पर नहीं लगती, बल्कि बच्चे के मन और शिक्षा व्यवस्था के प्रति उसके विश्वास पर भी पड़ती है।

बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर स्पष्ट रोक लगाई गई है। इसलिए शिक्षा का अधिकार केवल विद्यालय में दाखिला लेने या कक्षा में बैठने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, बाल-हितैषी, भयमुक्त और गरिमामय वातावरण में शिक्षा प्राप्त करे। यदि तेनकासी (तमिलनाडु) की घटना में लगाए गए आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो यह केवल अनुशासन की सीमा का उल्लंघन नहीं, बल्कि छात्राओं के वैधानिक अधिकारों का गंभीर हनन होगा। अनुशासन के नाम पर किसी बच्चे के साथ शारीरिक या मानसिक हिंसा करना शिक्षा के मूल उद्देश्य को ही पराजित करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है तथा न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार को मानवीय गरिमा से जोड़ा है। अनुच्छेद 14 समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण की गारंटी देता है। बच्चे भी इन संवैधानिक संरक्षणों के अधिकारी हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय यानी यूएनसीआरसी को स्वीकार किया है, जिसके तहत बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण मिलना चाहिए। इसी भावना के अनुरूप भारतीय कानूनों में भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। जहां किसी बच्चे को पढ़ाई के नाम पर भय, अपमान या शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़े, वहां शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। बच्चे की गरिमा शिक्षा व्यवस्था की पहली शर्त होनी चाहिए।

बच्चे के पालन-पोषण और व्यक्तित्व निर्माण की जिम्मेदारी केवल माता-पिता की नहीं होती। बच्चा अपने दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा विद्यालय में बिताता है। इसलिए शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन उसके मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुशासन का अर्थ भय पैदा करना नहीं, बल्कि बच्चे को अपनी गलती समझने, उसे सुधारने और बेहतर व्यवहार के लिए प्रेरित करना है। संवाद, सहानुभूति, मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रोत्साहन से बच्चों में आत्म-अनुशासन विकसित किया जा सकता है। बेंत, धमकी, अपमान और डर से पैदा हुआ अनुशासन वास्तविक अनुशासन नहीं, बल्कि दबाव है। तमिलनाडु ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। 'इल्लम थेडी कल्वी' जैसी पहल शिक्षा को बच्चों के करीब ले जाने का प्रयास है। 'नान मुदलवन' युवाओं में कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने पर केंद्रित है, जबकि 'पुधुमई पेन' जैसी योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करती है। लेकिन इन योजनाओं की सफलता केवल नामांकन, परीक्षा परिणाम या उच्च शिक्षा में प्रवेश के आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती। यह भी देखना होगा कि जिस विद्यालय में बच्चा पहुंचता है, वहां उसे सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है या नहीं। एक ओर सरकार बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे और दूसरी ओर विद्यालय परिसर में उन्हें अपमान या हिंसा का सामना करना पड़े, तो नीति और व्यवहार के बीच गंभीर विरोधाभास पैदा होता है। ऐसी घटनाओं के बाद केवल संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई कर देना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक ऐसी घटना शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों की ओर संकेत करती है। इसलिए विद्यालयों में अनुशासन संबंधी नीतियों, बाल संरक्षण व्यवस्था और शिकायत निवारण तंत्र की व्यापक समीक्षा आवश्यक है।

प्रभावित छात्राओं को आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श और भावनात्मक सहयोग दिया जाना चाहिए। विद्यालय में पूर्व में प्राप्त शिकायतों और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिक्षकों को बाल अधिकारों, सकारात्मक अनुशासन और अहिंसक व्यवहार के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के लिए ऐसा शिकायत तंत्र उपलब्ध हो, जहां वे बिना भय के अपनी बात रख सकें। जिस बच्चे को शिक्षक से डर लगता है, उसके लिए शिकायत तंत्र का होना ही पर्याप्त नहीं; उस तंत्र पर उसका विश्वास होना भी जरूरी है।

मानवाधिकार की दृष्टि से किसी नाबालिग बच्चे की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा—ये सभी एक-दूसरे से जुड़े अधिकार हैं। कथित रूप से बेंत से पीटा जाना केवल शरीर पर चोट का मामला नहीं है। इससे बच्चे के भीतर भय, अपमान, आत्मविश्वास में कमी और विद्यालय से दूरी जैसी दीर्घकालिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किसी भी नाबालिग छात्र या छात्रा के साथ ऐसा कथित व्यवहार उसके बुनियादी मानवाधिकारों को प्रभावित करता है। इसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक शोषण से संरक्षण का अधिकार तथा सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा पाने का अधिकार शामिल हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक है। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य और उसका भविष्य किसी भी अनुशासनात्मक व्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि विद्यालय बच्चे को भयमुक्त वातावरण नहीं दे सकता, तो शिक्षा का अधिकार अधूरा है। और यदि अनुशासन के नाम पर बेंत उठती है, तो चोट केवल बच्चे को नहीं लगती—चोट शिक्षा व्यवस्था की आत्मा और मानवाधिकारों की बुनियाद पर लगती है।

लेखक हरियाणा मानवाधिकार आयोग से जुड़े हैं।

अब जेन-अल्फा, कहीं कोई वायरस तो नहीं!

जेन-जी 'मस्ती की पाठशाला' में मगन हो सबका मजाक उड़ाकर सबको हलकान करने लगा। उसकी मस्ती अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब जेन-अल्फा आ गया और गंभीर मांगें उठाने लगा।

नहीं जी नहीं, डर का माहौल हम क्यों बनाएंगे? हम कोई सरकार और पुलिस थोड़े ही हैं। और हम शासक पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी नहीं हैं कि आंदोलन-वांदोलन करने वालों को वायरस टाइप कुछ भी कह देंगे। वैसे तो जी, आंदोलन-वांदोलन करने वालों को प्रधानमंत्री जी ने जो 'आंदोलनजीवी' नाम दिया था, वही ठीक था। कहां किसी ने बुरा माना था। बल्कि उन्होंने तो उन्हें 'परजीवी' भी कह दिया था। और अब देखो, बच्चे 'वायरस' कहने तक का बुरा मान रहे हैं। इतना बुरा तो श्री इडियट्स वाले 'वायरस' ने भी नहीं माना था, जबकि वह तो प्रिंसिपल था!

हम तो जी बस आगाही कर रहे हैं कि भाई देख लो, कहीं सचमुच ही कोई वायरस तो नहीं आ गया है। क्योंकि अब जेन-जी के बाद जेन-अल्फा भी आंदोलन पर उतर आया है। स्कूलों में शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, साफ-सफाई और शौचालयों की मांग कर रहे हैं, बिजली और पंखों की मांग कर रहे हैं।

एक जमाना था जब आंदोलन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हुआ करते थे और वो भी किस मांग पर—वीसी हटाओ, फीस घटाओ, हॉस्टलों में अच्छा खाना दो, बस पास दो—जैसी मांगों पर। युवा रोजगार मांगने के लिए आंदोलन करते थे। तब दो ही तो आंदोलनकारी तबके थे—छात्र तथा युवा, और फिर मजदूर। फिर किसान भी आंदोलन करने लगे। बल्कि वे तो इन दोनों तबकों से भी आगे निकल गए।

किसानों से यह कहकर कि भाई माफ करो, हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, सरकार ने यह मान लिया था कि चलो आंदोलन-वांदोलन से पीछा छूटा। 'परजीवी' कहे जाने पर 'आंदोलनजीवी' भी शर्मिंदा होकर घर बैठ ही जाएंगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि पता नहीं कहां से जेन-जी उठ खड़ा हुआ। और ऐसा उठा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर भी चुप होकर नहीं बैठा है।

ऊपर से अब यह जेन-अल्फा उठ खड़ा हुआ। कहां तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे, खुद नीति आयोग ने मान लिया था। तो इधर सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे और उधर टीवी शोज़ में नई-नई पाठशालाएं लगने लगी थीं। देश टीवी का दर्शक न रहकर छात्र बन गया था और सारे सबक रट रहा था, तभी जेन-जी और अब जेन-अल्फा उठ खड़े हुए। टीवी की पाठशालाओं के सारे सबक बेकार गए।

जेन-जी 'मस्ती की पाठशाला' में मगन हो सबका मजाक उड़ाकर सबको हलकान करने लगा। उसकी मस्ती अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब जेन-अल्फा आ गया और कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों की तरह गंभीर मांगें उठाने लगा। लक्षण अच्छे नहीं हैं जी, एकदम वायरस वाले हैं। सचमुच...!

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें...

वरिष्ठजन कल्याण महासंघ का गरिमामय आयोजन संपन्न

भिलाई। वरिष्ठजनों, महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित बहुआयामी संस्था वरिष्ठजन कल्याण महासंघ के तत्वावधान में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की पूर्व संध्या पर सियान सदन, हाउसिंग बोर्ड, भिलाई में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरिष्ठजनों के सम्मान, साहित्य, संगीत, योग एवं आत्मरक्षा जैसे विविध कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से समाज में वरिष्ठजनों की महत्ता को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। महासंघ के पदाधिकारियों ने मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में मंच पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. परदेशी राम वर्मा, आचार्य डॉ. महेश चंद्र शर्मा, डॉ. डी.पी. देशमुख, डॉ. नीलकंठ देवांगन, हेमलाल साहू 'निर्मोही', महासंघ अध्यक्ष घनश्याम कुमार देवांगन, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता एवं कांतिलाल विश्वकर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित वैचारिक संगोष्ठी का विषय वरिष्ठजन अनुभव की पूंजी और समाज की अमूल्य धरोहर था। संगोष्ठी का आधार वक्तव्य महासंघ के अध्यक्ष घनश्याम कुमार देवांगन ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजन बोझ नहीं, बल्कि समाज की अमूल्य धरोहर हैं।

संत रविदास जयंती पर मंडल स्तरों पर निकलेगी कलश यात्रा

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग जिला भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर से लाए गए पवित्र कलश का दुर्ग स्थित सतनामी आश्रम, सिविल लाइन रोड में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद दुर्ग जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए चार कलश तैयार कर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के मंडल अध्यक्षों को वितरित किए गए। इन कलशों को मंडल स्तर पर कलश यात्राओं के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कुरूद विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, भाजपा दुर्ग संभाग संगठन प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, विधायक ललित चंद्राकर, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशिला साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, महापौर अलका बाघमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, संत समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समाज को समानता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी का जीवन त्याग, भक्ति, श्रम और मानव कल्याण का प्रतीक है।

शिव महापुराण कथा सुनने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिले के भिलाई नगर स्थित जयंती स्टेडियम के समीप आयोजित शिव महापुराण कथा सुनने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह पहुंचे।

उन्होंने आम जनता के बीच बैठकर कथा श्रवण किया और महाआरती में शामिल होकर प्रदेश वासियों के खुशहाली के लिए भगवान भोले शंकर से कामना की। डॉ. सिंह ने प्रदेश की जनता की ओर से कथा वाचक पं.प्रदीप मिश्रा का भिलाई आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मिनी इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भिलाई के लोगों में सामप्रदायिक सामन्जस्य यहाँ की पहचान है।

उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए पवित्र श्रावण मास में कथा श्रवण हेतु उपस्थित शिव भक्तों के विशाल जनसमुदाय को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, श्रीमती रमशीला साहू तथा श्रीमती कौशिल्या देवी साय, आयोजन समिति के दयासिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

रिमझिम सावन मेला के शुभारंभ में सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय एवं डॉ. सरोज पाण्डेय हुईं शामिल, सावन झूले का लिया आनंद

महापौर अलका बाघमार सहित निगम की व्यवस्थाओं की सराहना

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा आयोजित दो दिवसीय रिमझिम सावन मेला-2026 का शुभारंभ विवेकानंद सभागार में भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा डॉ. सरोज पाण्डेय तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर अलका बाघमार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कौशल्या देवी साय एवं डॉ. सरोज पाण्डेय का निगम की एमआईसी सदस्यों एवं पार्षदगण द्वारा गरिमामय स्वागत किया गया।

श्रीमती कौशल्या देवी साय,डॉ सरोज पांडेय के साथ महापौर अलका बाघमार ने सावन झूले का आनंद भी लिया। मेले में महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजक खेलों, प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं विभिन्न स्टॉलों की व्यवस्था की गई है, जिसका शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक आनंद लिया।

श्रीमती कौशल्या देवी साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की कला, संस्कृति एवं परंपराओं को सहेजने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सावन उत्सव हमारी संस्कृति और सभ्यता की खूबसूरत पहचान है। उन्होंने कहा कि दुर्ग का रिमझिम सावन मेला हर वर्ष नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आता है। यह आयोजन मनोरंजन, संस्कृति और सामाजिक एकता का सुंदर संगम बन चुका है।

उन्होंने कहा कि इस मेले ने दुर्ग शहर की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम दिया है और नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने महापौर अलका बाघमार सहित नगर निगम की पूरी टीम को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, ताकि हमारी लोक संस्कृति और परंपराएं सदैव जीवंत रहें।

डॉ. सरोज पाण्डेय ने कहा कि सावन मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि दुर्ग की आत्मा, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रमाण है। ऐसे आयोजन महिलाओं को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सावन मास में आयोजित यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के साथ ही लोक संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आयोजन को निरंतर जारी रखने की शुभकामनाएं दीं।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि रिमझिम सावन मेला की सफलता में शहरवासियों, निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं सभी स्टॉल संचालकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि यह मेला अब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि दुर्ग शहर की सांस्कृतिक पहचान और धरोहर बन चुका है।

महिलाओं ने खेलों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दिखाई प्रतिभा

रिमझिम सावन मेले में महिलाओं ने तीज क्वीन, दौड़, कुर्सी दौड़ सहित विभिन्न मनोरंजक खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लोकगीत एवं लोकनृत्य की प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और पूरा सभागार सावन के उल्लास से गूंज उठा। मेले के दूसरे दिन 22 अगस्त को भी महिलाओं के लिए बिंदी लगाओ प्रतियोगिता, मटका फोड़, मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता, हौजी एवं चम्मच दौड़ सहित अनेक मनोरंजक खेल आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में भाग लेने की इच्छुक महिलाएं सुबह 9 बजे अपना पंजीयन करा सकेंगी।

'नराकास, भिलाई-दुर्ग' की 63वीं छमाही बैठक एवं वार्षिक पुरस्कार समारोह संपन्न

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग' (नराकास) की 63वीं छमाही बैठक एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 21 अगस्त 2026 को भिलाई इस्पात संयंत्र के सिविक सेन्टर स्थित भिलाई निवास के 'बहुउद्देशीय सभागार' में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) भिलाई इस्पात संयंत्र एवं कार्यकारी अध्यक्ष, 'नराकास, भिलाई-दुर्ग' पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में महाप्रबंधक प्रभारी (संपर्क, प्रशा. एवं जनसंपर्क) अमूल्य प्रियदर्शी उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथिगण ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तत्पश्चात अमूल्य प्रियदर्शी एवं राघवेन्द्र कुमार गर्ग, ने शॉल, श्रीफल व पुस्तक भेंटकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए राघवेन्द्र कुमार गर्ग ने कहा कि, नराकास, भिलाई-दुर्ग के सदस्य संस्थानों ने राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में सदैव उत्कृष्ट व प्रशंसनीय भूमिका का निर्वहन किया है। इसी का परिणाम है कि, नराकास, भिलाई-दुर्ग को नियमित रूप से अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान प्राप्त होने का क्रम बना हुआ है। नराकास परिवार हिंदी में समस्त कार्यालयीन कामकाज सहित अपने समस्त कार्यों में श्रेष्ठ निष्पादन करें तथा निरंतर नए शिखरों को स्पर्श करे, हमारा यही हम सबका सतत् प्रयास है। बैठक की कार्यवाही में सर्वप्रथम विगत बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन एवं आगत तिमाही के लिए कार्यसूची का वाचन किया गया।

विधायक ललित चंद्राकर ने किया भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

श्रीकंचनपथ न्यूज

रिसाली। रिसाली निगम क्षेत्र के मैत्रीनगर, शक्ति विहार, लक्ष्मी नगर और इस्पात नगर वार्ड में दो करोड़ पचपन लाख पच्चीस हजार की राशि से सड़क, नाली, सड़क चैड़ीकरण, सामुदायिक भवन, सौंदर्यीकरण और उद्यान संधारण के कार्य किए जाऐंगे। शुक्रवार को दुर्ग ग्रामीण विधायक वार्डों तक पहुंचे और विकास कार्यों की नींव रखी। उन्होंने रिसाली निगम क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को आम जनता को समर्पित किया।

इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वपरि है। उन्होंने चुनावी दौरे

का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें क्षेत्र के मतदाताओं ने जिताया है। जबसे वें विधायक बने है लगातार विकास कार्यो की भूमिपूजन प्राथमिकता के आधार मे कर रहे है।

उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वें जल्द ही लोकार्पण करने भी आऐंगे। उन्होंने पूरे 40 वार्डों में बिना भेदभाव के स्वीकृत कार्यो को पूरा कराने पर जोर दिया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, पार्षद सुनंदा चंद्राकर, डॉ. सीमा साहू, अनूप डे, विलास राव बोरकर, धर्मेन्द्र भगत, गजेन्द्री कोठारी, ममता सिन्हा, मनीष यादव, शीला नारखेड़े, सविता ढवस, रमा साहू, ईश्वरी साहू, सरिता देवांगन समेत मंडल अध्यक्ष अनुपम साहू, राजू जंघेल आदि उपस्थित थे।

इन वार्डों में होगा विकास कार्य: रिसाली निगम क्षेत्र के वार्डे क्र. 27 मैत्रीनगर में 44 लाख 9 हजार से नाली, पॉथवे निर्माण, गार्डन निर्माण, सौंदर्यीकरण और पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य होगा। इसी तरह वार्ड 28 शक्ति विहार में डोम शेड, नाली, पेवर ब्लॉक, पुलिया निर्माण, सड़क संधारण, उद्यान नवीनीकरण, नाली निर्माण आदि कार्य 01 करोड़ 08 लाख 89 हजार, वार्ड 29 लक्ष्मी नगर में 62 लाख 14 हजार और वार्ड 30 इस्पात नगर में 39 लाख 32 हजार से विकास कार्य होंगे।

पार्षद ने किया अभिनंदन: इस्पात नगर वार्ड पार्षद अनुप डे ने दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर को विकास कार्य की सौगात देने के लिए अभार व्यक्त किया। पार्षद ने भूमिपूजन कार्यक्रम में विधायक का नागरिकों की ओर से अभिनंदन किया। शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया।

जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कृषकों को समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना कृषि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्तमान में जिले में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों का वितरण शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रत्येक समिति के स्टॉक की दैनिक स्तर पर कड़ाई से मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी क्षेत्र में कृत्रिम किल्लत जैसी स्थिति निर्मित न हो सके। किसानों को उनकी पात्रता, जोत की भूमि और वास्तविक मांग के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ खाद का वितरण किया जा रहा है।

उप संचालक कृषि के अनुसार अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति कुम्हारी में गत वर्ष 283.89 मे.टन खाद वितरण की तुलना में इस वर्ष 780.21 मे.टन खाद भण्डारण कर 556.36 मे.टन खाद का वितरण किया गया है। इसीप्रकार सेवा सहकारी समिति गोंढ़ी में गत वर्ष 339.40 मे.टन खाद वितरण की तुलना में इस वर्ष 303.08 मे.टन खाद भण्डारण कर 266.61 मे.टन खाद का वितरण किया गया है। सेवा सहकारी समिति ओटेबंद में गत वर्ष 410.65 मे.टन खाद वितरण की तुलना में इस वर्ष 530.33 मे.टन खाद भण्डारण कर 479.19 मे.टन खाद का वितरण किया गया है। सेवा सहकारी समिति अहिवारा में गत वर्ष 418.60 मे.टन खाद वितरण की तुलना में इस वर्ष 420.28 मे.टन खाद भण्डारण कर 406.89 मे.टन खाद का वितरण किया गया है। सेवा सहकारी समिति अहेरी में गत वर्ष 467.44 मे.टन खाद वितरण की तुलना में इस वर्ष 360.00 मे.टन खाद भण्डारण कर 288.80 मे.टन खाद का वितरण किया गया है। उपरोक्त समितियों के गत वर्ष के कुल वितरण से इस वर्ष वर्तमान स्थिति में 473.92 मे.टन खाद अधिक भण्डारण कर 77.87 मे.टन खाद अधिक वितरण किया गया है। सहकारी समितियों के मांग के अनुसार उर्वरक भण्डारण कार्य लगातार किया जा रहा है। साथ ही जिले में खरीफ2025 पूरे मौसम में 65132 मे.टन खाद का वितरण हुआ था जबकि खरीफ 2026 में 67880 मे.टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध अद्यतन स्थिति में 69456 मे.टन खाद भण्डारण कर 48205 मे.टन खाद का वितरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा नकली एवं घटिया खाद की बिक्री को रोकने के लिये उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है जो निजी विक्रेताओं और समितियों की निरंतर जांच कर रही है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में नई श्रम संहिताओं एवं श्रमिक कल्याण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीएसपी में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की केंद्रीय टीम के भिलाई प्रवास के दौरान 21 अगस्त 2026 को नई श्रम संहिताओं एवं उनके अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों एवं श्रमिकों को नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों से अवगत कराना तथा श्रमिक कल्याण, संहिताओं के क्रियान्वयन और इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर केंद्रीय टीम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सार्थक संवाद का अवसर प्रदान करना था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तीन सदस्यीय केंद्रीय टीम का नेतृत्व निदेशक (श्रम सुधार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय डॉ. पी. के. जेना ने किया। टीम में अवर सचिव, एलआरसी संजय कुमार तिवारी तथा श्रम कल्याण आयुक्त (मुख्यालय), पीएमयू-एलआरसी ओ. पी. सिंह शामिल

रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन), भिलाई इस्पात संयंत्र संजय द्विवेदी ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यपालक निदेशक (रावघाट), सेल-भिलाई अरुण कुमार ने उपस्थितजनों को संबोधित किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि सांसद, दुर्ग विजय बघेल तथा श्रम प्रशासन एवं श्रमिक कल्याण से जुड़े विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ अधिकारीगण उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) बी. सी. नायक, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अखिलेश राय, सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) पी. के. दीक्षित, आरपीएफसी-II, ईपीएफओ गौरव डोगरा, उप निदेशक, ईएसआईसी रत्नेश राजन्या, उप निदेशक, ईएसआईसी एन. के. धीरेन्द्र पटनायक, तथा उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ शासन मनीष कुंजाम उपस्थित रहे ।

भिलाई इस्पात संयंत्र की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की। बीएसपी के मानव संसाधन अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी तथा कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग अथॉरिटीज भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, एनएसपीसीएल एवं एसआरयू के कर्मचारियों और श्रमिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इससे कार्यक्रम में भिलाई औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े व्यापक कार्यबल की सहभागिता सुनिश्चित हुई और संवाद को अधिक समावेशी स्वरूप मिला।

भिलाई इस्पात संयंत्र की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की। इस अवसर पर बीएसपी के मानव संसाधन अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी तथा कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग अथॉरिटीज भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, एनएसपीसीएल एवं एसआरयू के कर्मचारियों और श्रमिकों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर पहलों एवं श्रमिक कल्याण के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर केंद्रित एक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई, जिसके पश्चात सहायक प्रबन्धक (मानव संसाधन) श्री के. शशांक राव द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात निदेशक (श्रम सुधार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डॉ. पी. के. जेना ने नई श्रम संहिताओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने नई श्रम संहिताओं के विधायी ढांचे, प्रमुख प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी उपायों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित संवाद एवं प्रश्नोत्तरी सत्र के माध्यम से कर्मचारियों, श्रमिकों तथा विभिन्न सहभागी संगठनों एवं यूनियनों के प्रतिनिधियों ने नई श्रम संहिताओं, उनके कार्यान्वयन तथा श्रमिक कल्याण से जुड़े विषयों पर केंद्रीय टीम के अधिकारियों के साथ सीधे संवाद किया और अपने प्रश्न एवं संबंधित मुद्दे रखे।

Since 1972
CROWN®-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

विरासत का प्रवाह' राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

रायपुर। संस्कृति विभाग, पुरातत्त्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के तत्वावधान में विरासत का प्रवाह: नैतिकता, संरक्षण और समुदाय विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विषय-विशेषज्ञों, विद्वानों, शोधकर्ताओं एवं प्रतिभागियों ने विरासत संरक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान विरासत संरक्षण में नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रामाणिकता तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर विशेष रूप से चर्चा हुई। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन एवं परिचय पुरातत्त्ववेत्ता प्रभात कुमार सिंह ने दिया। उन्होंने संगोष्ठी की विषय-वस्तु पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विरासत केवल अतीत की स्मृतियों और पुरावशेषों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक पहचान, ज्ञान और सांस्कृतिक निरंतरता का आधार है। विरासत के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सहभागिता तथा भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कोनगुड़ में विकसित हो रहा आकांक्षा ग्रामीण कौशल एवं नवाचार केंद्र

रायपुर। कोण्डागांव, जिले के सुदूर कोनगुड़ में नीति आयोग के सौजन्य से आकांक्षा ग्रामीण कौशल एवं नवाचार केंद्र विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दूरस्थ एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का स्थायी मॉडल विकसित करना है। विकासखंड फरसगांव के ग्राम कोनगुड़ में स्थापित किए जा रहे इस केंद्र के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से 1,500 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने तथा 300 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुवार को कांकेर सांसद भोजराज नाग एवं विधायक नीलकंठ टेकाम ने केंद्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण चरण में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र भ्रमण के लिए आए पुनर्वासित व्यक्तियों से भी चर्चा की और उन्हें रोजगार से जुड़कर मुख्यधारा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

नौनिहालों के सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ा कदम, पाटन में 28.38 लाख के निर्माण कार्य मंजूर

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिला दुर्ग के जनपद पंचायत पाटन के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। नौनिहालों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु सोनपुर, करेला एवं केसरा में कुल 28.38 लाख रुपये के निर्माण कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत कार्यों के तहत सोनपुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं करेला एवं केसरा में अभिसरण के तहत नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्रत्येक भवन हेतु 11.69 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत 8 लाख रुपये तथा डीएमएफ के तहत 2 लाख रुपये सहित अन्य मदों से राशि का अभिसरण किया गया है। आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में संपत्ति की मालकिन बन रही महिलाएं, आर्थिक सशक्तिकरण को मिली नई मजबूती

श्रीकंचनपथ न्यूज

मुख्यमंत्री साय की पहल का असरः महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में लगभग 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और संपत्ति स्वामित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लिए गए निर्णय के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने से प्रदेश में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन का रुझान बढ़ा है। इससे महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा मिलने के साथ ही नागरिकों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, 06 मई से 27 जुलाई 2026 की अवधि में महिलाओं के नाम 30 हजार 720 दस्तावेज पंजीकृत किए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 20 हजार 319 थी। इस प्रकार महिलाओं के नाम पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में लगभग 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 06 मई से 27 जुलाई 2025 की अवधि में कुल 63 हजार 174 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए थे, जिनमें 20 हजार 319 दस्तावेजों में महिलाएं खरीदार थीं। महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेखों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत थी। इसी अवधि में वर्ष 2026 में कुल 74 हजार 424 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए, जिनमें 30 हजार 720 दस्तावेजों में महिलाएं खरीदार थीं। इससे महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है। यानी एक वर्ष में महिलाओं की हिस्सेदारी में 9 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए सुधार के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। संपत्ति में महिलाओं का बढ़ता स्वामित्व उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ परिवार में उनकी निर्णयात्मक भूमिका को भी मजबूत करता है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिखाई दे रहा है। विभागीय विश्लेषण के अनुसार प्रदेश के लगभग 75 प्रतिशत जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 20 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। जांजगीर-चांपा, बालोद, कोरिया, रायपुर और कांकेर सहित अनेक जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जिला-वार आंकड़ों में रायपुर में महिलाओं के नाम पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 4,220 से बढ़कर 6,038, बिलासपुर में 1,894 से बढ़कर 2,958 तथा जांजगीर-चांपा में 1,239 से बढ़कर 2,302 हुई है। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व के प्रति बढ़ते रुझान का पता चलता है।

महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजीयन शुल्क में दी जा रही 50 प्रतिशत की छूट से नागरिकों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिली है। 06 मई से 27 जुलाई 2026 की अवधि में इस छूट के माध्यम से नागरिकों को 76 करोड़ 95 लाख 33 हजार 689 रुपये, यानी लगभग 76.95 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें परिवार तथा समाज में समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस निर्णय के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि यह पहल परिवारों को महिलाओं के नाम संपत्ति स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित कर रही है। संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है तथा परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका को और सशक्त बनाता है।

नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता के बाद बस्तर में विकास की नई गति : मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई औद्योगिक नीति से निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को मिला नया विस्तार

रायपुर। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास की दौड़ में पीछे रहे बस्तर में अब शांति, विश्वास और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। सुरक्षा के साथ-साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। बस्तर की प्राकृतिक संपदा, संस्कृति और पर्यटन की संभावनाओं को विकास से जोड़कर क्षेत्र के लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री साय ने विगत दिवस मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पत्र सूचना कार्यालय, चेन्नई के निदेशक पी. अरुण कुमार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए चेन्नई के पत्रकारों के दल से चर्चा के दौरान यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से छत्तीसगढ़ में विकास की बदलती तस्वीर, बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध मिली सफलता के बाद तेज हुई विकास गतिविधियों, राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति, निवेश एवं रोजगार की संभावनाओं तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे विस्तार पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लगभग चार दशकों तक नक्सलवाद ने बस्तर के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी

सुविधाएं पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के साहस और स्थानीय लोगों के बढ़ते विश्वास से बस्तर तेजी से शांति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी नक्सलवाद के कारण शासन की पहुंच कठिन थी, वहां आज विकास की योजनाएं तेजी से पहुंच रही हैं। सुरक्षा कैंपों के आसपास के गांवों में 'नियद नेल्लानार' योजना के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, राशन, बैंकिंग और आजीविका की सुविधाओं में वृद्धि हुई है। सरकार का लक्ष्य केवल नक्सलवाद का अंत करना नहीं, बल्कि बस्तर में विकास और समृद्धि की ऐसी मजबूत नींव तैयार करना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतर हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, वन संपदा, जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं की विशिष्ट पहचान है। शांति स्थापित होने के साथ पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता के लिए नए अवसर बन रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि बस्तर की विशिष्टताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले तथा पर्यटन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर सृजित हों।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पत्रकारों को राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज, वन और कृषि संपदा से समृद्ध होने के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर है। राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में रोजगार सृजन, स्थानीय संसाधनों के मूल्य संवर्धन और नए एवं उभरते क्षेत्रों के उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरल प्रक्रियाओं और उद्योग अनुकूल वातावरण के कारण देश-विदेश के निवेशकों का छत्तीसगढ़ के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि राज्य अब परंपरागत उद्योगों तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं तेजी से विकसित हो रही हैं। पर्याप्त विद्युत उपलब्धता, मजबूत अधोसंरचना, देश के मध्य में भौगोलिक स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए अनुकूल बनाती है। सरकार का विशेष जोर ऐसे निवेश पर है, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर तैयार हों।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि रायपुर और नवा रायपुर देश के महत्वपूर्ण एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के इन संस्थानों की उपलब्धता से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर अपने ही राज्य में मिल रहे हैं।

बाल विवाह रोककर प्रशासन ने बचाया नाबालिग का भविष्य

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में सुकमा जिले के तोंगपाल क्षेत्र में प्रशासन की तत्परता से एक 16 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रुकवाकर उसे सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया गया।

सुकमा जिले के मासापारा कावराकोपा क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने दोनों पक्षों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश के बाद युवक पक्ष ने विवाह स्थगित करने पर सहमति जताई। जानकारी के अनुसार सुकमा जिले के महारापारा हमीरगढ़ निवासी 16 वर्षीय बालिका को विवाह के उद्देश्य से युवक अपने साथ लेकर आया था। प्रशासनिक टीम ने बालिका की सुरक्षा और सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए उसे उसके गृहग्राम पहुंचाया। वहां परिजन उपस्थित नहीं मिलने पर बालिका को सुरक्षित रूप से सुकमा लाया गया। बाल कल्याण समिति के समक्ष आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने तक उसे सखी सेंटर में सुरक्षित आश्रय दिया गया है।

कार्रवाई के दौरान घोषणा-पत्र लिया गया और पंचनामा तैयार किया गया। संबंधित पक्षों को बाल विवाह करने पर होने वाली वैधानिक कार्रवाई से भी अवगत कराया गया। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुकमा और जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में संरक्षण अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, चाइल्ड लाइन परियोजना समन्वयक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम सचिव और रोजगार सहायक शामिल रहे।

बिहान से कम लागत में राखी निर्माण को मिला नया आयाम, आत्मनिर्भर बन रहीं ग्रामीण महिलाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अपनी पारंपरिक दक्षता और स्थानीय संसाधनों को आजीविका के अवसरों में बदल रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं कृषि एवं अन्य गतिविधियों के साथ-साथ मौसम और त्योहारों के अनुरूप सीजनल व्यवसाय अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत किशुन नगर की जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसी बदलाव की प्रेरक मिसाल हैं।

रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए समूह की 12 महिलाएं इन दिनों घरेलू एवं स्थानीय संसाधनों से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। कम लागत में तैयार इन राखियों को स्थानीय बाजार में स्टॉल लगाकर और घर से विक्रय किया जा रहा है। इससे महिलाओं को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है और उनकी आजीविका को मजबूती मिल रही है। समूह की सदस्य सुश्री सोनाली सिंह ने बताया कि समूह की महिलाएं वर्षभर मौसम और त्योहार के अनुसार अलग-अलग आजीविका गतिविधियां अपनाती हैं। वर्तमान में राखी निर्माण

का कार्य किया जा रहा है। राखियां तैयार करने में चावल, गेहूं, मक्का, कोहड़े के बीज सहित घर में उपलब्ध अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। इन सामग्रियों को रंग एवं सजाकर आकर्षक डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा रेशमी धागे, ऊन और अन्य सजावटी सामग्री आवश्यकतानुसार बाजार से खरीदी जाती है।

सुश्री दीप्ति चौधरी ने बताया कि घरेलू सामग्री के उपयोग से राखियों की उत्पादन लागत कम रहती है। समूह की महिलाएं अपने खाली समय में एक साथ बैठकर राखियां तैयार करती हैं। त्योहार के दौरान मांग बढ़ने पर उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। तैयार उत्पादों की बिक्री स्टॉल और घर से की जाती है।

कांवड़ यात्रा आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक : मंत्री राजेश अग्रवाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पावन श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। इसी क्रम में रामगढ़ से कैलाश गुफा की ओर कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने आत्मीय स्वागत एवं सत्कार किया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से मुलाकात कर उनकी यात्रा के संबंध में जानकारी ली और सभी श्रद्धालुओं को सुखद, सुरक्षित एवं सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, तपस्या और समर्पण की यात्रा है। भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास इस यात्रा में दिखाई देता है। कांवड़ यात्री कठिन परिस्थितियों और

लंबी दूरी की चुनौतियों के बावजूद पूरे उत्साह एवं श्रद्धाभाव के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यह यात्रा श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा और भगवान भोलेनाथ के प्रति उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है।

उन्होंने कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हुए भगवान भोलेनाथ से सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद, सुरक्षित एवं सफल होने की कामना की। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ सभी कांवड़ यात्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।

कांवड़ यात्रियों में दिखा उत्साह और भक्तिभावः रामगढ़ से कैलाश गुफा की ओर बढ़ रहे कांवड़ यात्रियों में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव के साथ कांवड़ लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं का स्वागत, सेवा और सत्कार भी किया जा रहा है। इससे यात्रा मार्ग पर भक्ति और सेवा का वातावरण बना हुआ है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक यात्राएं समाज में भाईचारे, सेवा, सद्भाव और एकजुटता की भावना को मजबूत करती हैं। कांवड़ यात्रियों की सेवा करना, उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका उत्साह बढ़ाना भी भगवान शिव की भक्ति का ही एक रूप है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में श्रद्धा, सेवा और सामुदायिक सहभागिता का विशेष महत्व रहा है।

उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, अनुशासन बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और यात्रा मार्ग पर दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर पूरा वातावरण भक्तिमय रहा और 'हर हर महादेव' के जयकारों से गूंजता रहा।

जशपुर में होमस्टे पर्यटन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती

श्रीकंचनपथ न्यूज

जिला प्रशासन की पहल रंग लाई, स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अनुभव लेने पर्यटकों का बढ़ रहा रुझान

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल में जशपुर जिले में पर्यटन विकास को ग्रामीण आजीविका से जोड़ने की दिशा में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विकसित किए जा रहे होमस्टे अब स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय का नया माध्यम बनने के साथ ही जशपुर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक खान-पान और ग्रामीण जीवनशैली को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं।

जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल देशदेखा के समीप स्थित केरे गांव में विकसित ग्रामीण होमस्टे ने विशेष पहचान बनाई है। यहां 4 फरवरी 2026 को अंतरिक्ष यात्री एवं अशोक चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला तथा 4 अप्रैल 2026 को

राज्यपाल रमेन डेका ने होमस्टे का अवलोकन किया। दोनों विशिष्ट अतिथियों ने देशदेखा समूह की महिलाओं द्वारा पारंपरिक विधि से तैयार व्यंजनों का स्वाद लिया और स्थानीय आदिवासी संस्कृति, जनजीवन तथा आतिथ्य परंपरा का अनुभव किया। इससे ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को नई पहचान मिली है।

जशपुर में ग्रामीण एवं सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **Homestays of India** टीम द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। 25 जनवरी 2026 को **Homestays of India**, छत्तीसगढ़ सरकार एवं जशपुर जिला प्रशासन के बीच हुए समझौते के तहत केरे गांव को मॉडल कम्युनिटी टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित करने की पहल की गई है।

इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को केवल पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने तक सीमित न रखते हुए उन्हें स्थानीय ग्रामीण जीवन, खान-पान, परंपराओं, संस्कृति और प्रकृति से सीधे जोड़ना है। इससे पर्यटन का लाभ सीधे ग्रामीण समुदाय तक पहुंच रहा है। जशपुर के होमस्टे पर्यटकों को प्रकृति के करीब रहने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहे हैं।

यहां ट्रेकिंग, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ग्राम भ्रमण, कृषि कार्यों में सहभागिता, पारंपरिक भोजन एवं जनजातीय संस्कृति का अनुभव जैसी गतिविधियां उपलब्ध हैं।

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर

जिले में वर्तमान में केरे, छिछली र, दनगरी, मयाली और घोघरा (बलाझार) सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर होमस्टे विकसित एवं सूचीबद्ध हैं। इन होमस्टे के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आवास एवं आतिथ्य सेवाओं के साथ स्थानीय भोजन, गाइडिंग, प्रकृति भ्रमण और अन्य पर्यटन गतिविधियों से आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। पर्यटकों के बढ़ते रुझान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ महिला सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार सृजन, सांस्कृतिक संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करने में भी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

पैसा और प्यार में से किसको चुनेंगी निया शर्मा?

टीवी अभिनेत्री ने दिया दो-टूक जवाब, फैंस ने भी दी प्रतिक्रिया

निया शर्मा टीवी की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जो अपने बोल्ड लुक और बयानों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में निया शर्मा ने बताया कि वह प्यार और पैसे में से किसका चुनाव करेंगी?

निया शर्मा को टीवी सीरियल 'जमाई राजा' और 'नागिन 4' के जरिए घर-घर पहचान मिली थी। इसके अलावा वह कई रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं। हाल ही निया 'लाफ्टर शेफ' के सेट पर नजर आईं। यहां पैपराजी ने उनसे सवाल किया कि वह प्यार और पैसे में से किसे चुनेगी? इस पर क्या रहा अभिनेत्री का जवाब, जानिए?

पैसे और प्यार में से निया ने किसे दी अहमियत?

पैपराजी के सामने निया शर्मा नारंगी रंग के सूट-सलवार में आईं। वह 'लाफ्टर शेफ' का एपिसोड शूट करने आई थीं। इस सेट पर उन्होंने पैपराजी को कहा, 'वह प्यार और पैसे मे से पैसे को चुनेंगी।' वह आगे कहती हैं, 'वह हमेशा पैसे को ही चुनेंगी।'

फैंस ने अभिनेत्री के जवाब पर क्या प्रतिक्रिया दी?

जब फैंस ने निया शर्मा जवाब सुना तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें सही बताया। इसके अलावा कुछ फैंस ने निया के लुक को सराहा और हार्ट इमोजी शेयर किए। निया शर्मा की इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उनके लगभग 8 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं।

'नागिन 4' में निया शर्मा ने लीड रोल किया था। अब तक इस टीवी शो के सात सीजन आ चुके हैं, जिनमें मौनी रॉय के अलावा, सुरभि ज्योति, सुरभि चांदना, अदा खान, तेजस्वी प्रकाश और प्रियंका चाहर चौधरी ने लीड रोल किए थे।

बीते दिनों इस शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने एक वीडियो में सभी अभिनेत्रियों की झलक दिखाई है। साथ ही बताया कि वह इसे टीवी से आगे लेकर जाना चाहती हैं। हालांकि, एकता कपूर ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह 'नागिन' पर कोई फिल्म बनाएंगी या वेब सीरीज।

भाग्यश्री बोर्से के हाथ से फिसली आदित्य रॉय कपूर की फिल्म?

साउथ की चर्चित अभिनेत्री भाग्यश्री बोर्से और बॉलीवुड अभिनेता आदित्य रॉय कपूर, डायरेक्टर मिलाप जवेरी की आगामी फिल्म का हिस्सा होंगे। फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट पर आधारित यह खबर पिछले दिनों खूब चर्चा में रही। लेकिन अब नया अपडेट इस बारे में सामने आया है। इस फिल्म को लेकर टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है।

मेकर्स ने अभिनेत्री भाग्यश्री बोर्से को लेकर क्या कहा?

टी-सीरीज के एक प्रवक्ता ने कहा, 'आदित्य रॉय कपूर के साथ टी-सीरीज और मिलाप जवेरी एक फिल्म बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में भाग्यश्री बोर्से के शामिल होने की खबरें गलत हैं। प्रोडक्शन हाउस जल्द ही अभिनेत्री के नाम का आधिकारिक घोषणा करेगा।'

क्या पहले भी हिंदी फिल्में कर चुकी हैं भाग्यश्री बोर्से?

भाग्यश्री बोर्से तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में अभिनय करती हैं। वह बॉलीवुड में 'यारियां 2' और 'चंदू चैंपियन' में छोटे लेकिन अहम किरदार निभा चुकी हैं।

वहीं फिल्म विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम' का भी वह हिस्सा रही हैं। वह एक तमिल फिल्म 'सियोन' भी कर रही हैं।

बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद अभिनय में आईं अभिनेत्री

भाग्यश्री बोर्से का जन्म भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद (अब छत्रपति संभाजीनगर) में हुआ था। वह सात साल तक नाइजीरिया के लागोस में रहीं, वहां अपनी स्कूली शिक्षा का बड़ा हिस्सा पूरा किया।

बाद में मॉडलिंग करते हुए उन्होंने मुंबई में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट में करियर ना बनाकर, फिल्मों में कदम रखा।

रिया चक्रवर्ती बोलीं- देश में सबसे ज्यादा ट्रोलिंग मैंने सही है, दुनिया मुझे गद्दार मानती है

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती इन दिनों रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आ रही हैं। वर्ष 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया था। मामले की जांच के दौरान रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। बाद में मामले में रिया के खिलाफ आरोपों को लेकर उन्हें राहत मिली। अब शो के पांचवें एपिसोड में रिया ने बताया कि वह 'गद्दार' की भूमिका क्यों नहीं निभाना चाहतीं। शो में श्वेता तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए रिया ने कहा कि वह गद्दार नहीं बनना चाहतीं, क्योंकि दुनिया पहले ही उन्हें गद्दार मान चुकी है। उन्होंने कहा कि यह बात उनके निजी जीवन के अनुभवों से जुड़ी है।

रिया के अनुसार, वह किसी मनोरंजन कार्यक्रम में आकर अपनी इच्छा से किसी की 'हत्या' जैसी भूमिका नहीं निभाना चाहतीं, क्योंकि इससे उनके खिलाफ फिर से नकारात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोग इस पर भी आपत्तिजनक मजाक और मीम बना सकते हैं।

रिया ने खुद को देश में सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाने वाली हस्तियों में से एक बताते हुए कहा कि वह फिर से उसी तरह के दौर से नहीं गुजरना चाहतीं। रिया ने शो के अन्य प्रतिभागियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह गद्दार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है कि लोगों ने उन्हें गद्दार समझा, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष बताया गया।

उनका यह बयान सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और उसके बाद हुई जांच की ओर इशारा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बाद में मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके बाद रिया को बड़ी राहत मिली।

कब रिलीज होगी तापसी पन्नू की फिल्म 'गांधारी' दिखेगी मुश्किलों से लड़ती एक मां की कहानी

फिल्म 'अस्सी' के बाद तापसी पन्नू अपकमिंग फिल्म 'गांधारी' में नजर आने वाली हैं। मेकर्स ने इसकी रिलीज की तारीख का एलान कर दिया है। उन्होंने इसकी कहानी के बारे में भी बताया है।

तापसी पन्नू की अदाकारी वाली फिल्म 'गांधारी' की रिलीज डेट सामने आ गई है। इश्वक सिंह, छाया कदम, स्वस्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और जतिन सरना मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके निर्देशक देवाशीष मखीजा हैं। जबकि इसकी लेखिका और निर्माता कनिका ढिल्लों हैं।

कब रिलीज होगी 'गांधारी'?

अपकमिंग फिल्म 'गांधारी' 3 सितंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। एक्शन-थ्रिलर फिल्म दिखाती है कि जब किसी महिला की प्यारी चीजें खतरे में हों, तो वह किस हद तक जा सकती है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि मां के प्यार से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं होती। वह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए जो सफर तय करती है, उससे ज्यादा मुश्किल कोई सफर नहीं होता।

एक काल्पनिक शहर 'जॉयपुरा' की पृष्ठभूमि पर आधारित, 'गांधारी' अटूट विश्वास, शांत सहनशक्ति और अदम्य साहस की कहानी है। कहानी के केंद्र में 'बानी' (तापसी पन्नू) है, एक ऐसी मां जिसकी ममता की परीक्षा हर मोड़ पर होती है। उसे पूरे यकीन और त्याग के साथ अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तापसी पन्नू के अब तक के सबसे मुश्किल फिजिकल रोल्स में से एक मानी जाने वाली इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का भी गहरा मेल है।

तापसी ने कनिका के साथ दोबारा किया काम

'फिर आई हसीन दिलरुबा' की सफलता के बाद, यह फिल्म नेटफ्लिक्स को कनिका ढिल्लों और तापसी पन्नू के साथ फिर से एक साथ लाती है। लेखिका और प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों ने कहा, 'गांधारी' के जरिए हम एक ऐसी महिला की कहानी बताना चाहते थे, जो अपनी परिस्थितियों से अपनी पहचान तय नहीं होने देती।

तापसी पन्नू को आखिरी बार फिल्म 'अस्सी' में देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा हैं। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। 30 करोड़ की लागत में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 13.43 करोड़ रुपये ही कमा सकी थी। आलोचकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी।

मुंह का स्वाद कड़वा क्यों हो जाता है? जानिए 5 कारण

मुंह का कड़वा स्वाद एक आम समस्या है, जिसे कई लोग अनुभव करते हैं। यह समस्या न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय हो सकती है, बल्कि आपके दिन की शुरुआत और खत्म होने का मजा भी बिगाड़ सकती है। इस लेख में हम कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनके कारण मुंह का स्वाद कड़वा हो सकता है, ताकि आप सही समय पर उपाय कर सकें और इस समस्या से राहत पा सकें।

कुछ दवाओं का सेवन

कुछ दवाओं का सेवन भी मुंह के कड़वे स्वाद का कारण बन सकता है, जैसे कि कुछ एंटी-एलर्जी की दवाएं या मन के तनाव को कम करने वाली दवाएं।

इन दवाओं के कारण मुंह सूख सकता है या पेट में एसिड बढ़ सकता है, जिससे कड़वाहट होती है। अगर आप नियमित रूप से कोई दवा ले रहे हों तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी सलाह अनुसार दवा बदलवाएं या उसकी मात्रा कम करवाएं।

जीभ की सफाई का ध्यान न रखना

जीभ की सफाई का ध्यान न रखना मुंह के कड़वे स्वाद का एक बड़ा कारण हो सकता है। अक्सर लोग ब्रश करते समय जीभ को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो जाती है।

इससे मुंह में कड़वाहट महसूस हो सकती है। इसलिए रोजाना ब्रश करते समय जीभ को भी साफ करें।

इसके लिए आप नरम ब्रश का उपयोग कर सकते हैं और हल्के हाथों से जीभ को साफ करें।

दांतों की समस्याएं

दांतों की समस्याएं जैसे कि दांतों में कीड़े लगना, मसूड़ों की सूजन या दांतों में दर्द भी मुंह के कड़वे स्वाद का कारण बन सकती हैं।

इन समस्याओं के कारण बैक्टीरिया पनपते हैं, जो कड़वाहट पैदा करते हैं। इसलिए नियमित रूप से दंत चिकित्सक से जांच करवाना जरूरी है ताकि इन समस्याओं का समय रहते पता चल सके और उनका इलाज हो सके।

इसके अलावा दांतों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दें।

पाचन तंत्र की खराब स्थिति

पाचन तंत्र की खराब स्थिति भी मुंह के कड़वे स्वाद का एक अहम कारण हो सकती है। जब पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता तो पेट में एसिड बढ़ने लगता, जो कड़वाहट पैदा करता है।

इसके अलावा खट्टी-मीठी चीजों का सेवन भी इस समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित रूप से पानी पिएं। साथ ही ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें।

धूम्रपान और शराब का सेवन

धूम्रपान और शराब का सेवन न केवल आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि ये मुंह में भी कड़वाहट पैदा कर सकता है।

तंबाकू और शराब के कारण मुंह में सूखापन आता है, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं और कड़वाहट महसूस होती है। इसलिए इन आदतों को छोड़ना जरूरी है ताकि आपके मुंह की स्थिति बेहतर हो सके और आप स्वस्थ रह सकें।

इसके अलावा धूम्रपान और शराब का सेवन कम करने के लिए चिकित्सा सहायता लें।

यूजर्स पर भड़कीं श्वेता तिवारी? राज ठाकरे से पूछा सवाल

श्वेता तिवारी ने इस बात पर चिंता जताई है कि महिलाओं को अपशब्द कहना इतना आम क्यों हो गया है। उन्होंने राज ठाकरे से एक सवाल पूछा है और मराठी संस्कृति पर बात की है।

टीवी की मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा के आम इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने सवाल किया कि लोग उन महिलाओं को नीचा दिखाने का हक कैसे समझते हैं, जिन्हें वे जानते भी नहीं हैं। 'द ट्रेटर्स 2' की प्रतिभागी श्वेता ने शो के दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत के दौरान अभद्र कमेंट्स देखे और फिर इस मुद्दे पर इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की।

श्वेता ने बताया कि हाल ही में वह 'द ट्रेटर्स 2' की अपनी को-कंटेस्टेंट पारुल गुलाटी के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आई थीं और वहां देखे गए कमेंट्स से वह परेशान हो गईं। उन्होंने कहा कि कई यूजर्स महिलाओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे।

अभिनेत्री ने यह भी कहा कि ऐसे कमेंट्स हमेशा अनपढ़ या मुश्किल बैकग्राउंड वाले लोग ही नहीं करते। उनके मुताबिक, ऐसी बातें कहने वाले कई लोग पढ़े-लिखे होते हैं, उनके परिवार और करीबी महिलाएं भी होती हैं, फिर भी वे दूसरी महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

अनजान महिला पर क्यों करते हैं कमेंट?

श्वेता ने खुद पर की गई अभद्र टिप्पणियों के बारे में भी बात की और कहा कि लोग कभी-कभी उनके बच्चों के बारे में भी परेशान करने वाली बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब वह ऐसे यूजर्स की प्रोफाइल देखती हैं, तो अक्सर उन्हें उनकी पत्नियों, बेटियों और परिवार के दूसरे सदस्यों की तस्वीरें दिखती हैं। उन्होंने सवाल किया, 'तो फिर किसी ऐसी महिला का अपमान करना कैसे सही हो सकता है जिसका आपसे कोई लेना-देना ही नहीं है?'

मराठी संस्कृति को लेकर क्या बोलीं श्वेता?

अभिनेत्री ने उन कुछ यूजर्स की पहचान के बारे में भी बात की जो ऑनलाइन महिलाओं को निशाना बनाते हैं। उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया जो गर्व से खुद को 'मराठी मानूस' कहते हैं और सवाल किया कि क्या ऐसा व्यवहार उस पहचान से जुड़े मूल्यों को दिखाता है। श्वेता ने कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी महाराष्ट्र में रही हैं और राज्य व मराठी संस्कृति से उनका गहरा जुड़ाव है। उन्होंने लिखा कि वह इस सोच के साथ बड़ी हुई हैं कि मराठी संस्कृति महिलाओं, उनकी ताकत और सम्मान का आदर करती है।

श्वेता ने राज ठाकरे से क्या सवाल किया?

उन्होंने राज ठाकरे से भी सीधे सवाल किया, 'राज ठाकरे, अगर ऐसे लोग आपके समर्थक हैं, तो मैं सच में जानना चाहूंगी... क्या आपको लगता है कि यह सही व्यवहार है?' श्वेता ने अपनी बात खत्म करते हुए जोर दिया कि सम्मान इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि कोई महिला व्यक्तिगत रूप से जानी-पहचानी है या उसे पसंद किया जाता है। उन्होंने लिखा, 'महिलाओं का सम्मान करें, सिर्फ उन महिलाओं का नहीं जिनसे आप प्यार करते हैं, बल्कि सभी महिलाओं का।'

खास-खबर

रक्षाबंधन पर बिहान की दीदियों ने थामा स्वावलंबन का धागा

रायपुर। रक्षाबंधन पर्व बिहान से जुड़ी ग्रामीण दीदियों के लिए भाई-बहन के स्नेह के साथ स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर भी लेकर आया है। गरियाबंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय एवं पारंपरिक सामग्री से आकर्षक राखियों का निर्माण कर रही हैं। राखियों के विक्रय से महिलाओं को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है और वे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मैनपुर विकासखंड में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राखी निर्माण एवं विक्रय की गतिविधि संचालित कर रही है। समूह द्वारा 5 हजार 340 रुपये की लागत से राखियां तैयार कर अब तक 11 हजार 258 रुपये की बिक्री कर चुकी है। इसी प्रकार विकासखंड गरियाबंद में संजीवनी संकुल संगठन जोबा से संबद्ध गायत्री स्व-सहायता समूह सढ़ौली की चार महिला सदस्य विभिन्न प्रकार की आकर्षक राखियों का निर्माण कर रही हैं। समूह द्वारा धान चावल, मूंगा, मटर, झरगा, सेमी, अरहर सहित अन्य स्थानीय सामग्री से राखियों की विभिन्न वैरायटी तैयार की गई है। इन राखियों की कीमत 5 रुपये से 60 रुपये तक निर्धारित की गई है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के क्रियान्वयन की सराहना

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान केन्द्रीय सचिव को राज्य के नगरीय निकायों में भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्यवन की जानकारी दी। बोरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) की प्रगति से अवगत कराए जाने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के कार्यों को विस्तारित कार्यावधि के भीतर पूर्ण कराने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी दी। राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद थे। प्रमुख सचिव बोरा ने सिंह से नई दिल्ली के 'संकल्प भवन' में हुई मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं अरबन चैलेंज फण्ड, मिशन अमृत और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेव्हल्पमेंट, पुरानी म्यूनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास एवं भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का चिन्हांकन किया गया है।

युवाओं को 'जॉब सीकर' नहीं, 'जॉब क्रिएटर' बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री

वर्ल्ड लीडर्स फोरम में छत्तीसगढ़ ने रखा युवा-केंद्रित अर्थव्यवस्था का रोडमैप, 6 लाख विद्यार्थियों को एआई प्रशिक्षण, वर्ष 2030 तक 5 हजार स्टार्टअप का लक्ष्य

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय वर्ल्ड लीडर्स फोरम में वैश्विक आर्थिक जगत की प्रमुख हस्तियों के समक्ष छत्तीसगढ़ की तेजी से बदलती आर्थिक तस्वीर, निवेश की व्यापक संभावनाओं और भविष्य के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपनी पारंपरिक औद्योगिक और खनिज आधारित पहचान से आगे बढ़कर युवा शक्ति, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक विनिर्माण पर आधारित नई अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल बड़े निवेश आकर्षित करना नहीं है, बल्कि निवेश को रोजगार, उद्यमिता, बेहतर आय और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ के युवा केवल रोजगार तलाशने वाले न रहें, बल्कि अपने नवाचार और उद्यमिता के बल पर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर

पैदा करें, इसी सोच के साथ राज्य की नीतियों और योजनाओं को नया स्वरूप दिया जा रहा है। फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित भारत और विश्व की अनेक प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 6.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और आर्थिक वृद्धि दर 11.57 प्रतिशत रही है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 1 लाख 79 हजार 244 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए विकास और जनकल्याण को समान प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के 1.72 लाख करोड़ रुपये के बजट में अधोसंरचना निर्माण, पूंजीगत व्यय और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क, रेल, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत कर छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में युवा हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा केवल नौकरी की प्रतीक्षा करने वाले 'जॉब सीकर' नहीं, बल्कि 'जॉब क्रिएटर' बनें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2030 तक 5 हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नए उद्यमियों को अपने अभिनव विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए 10 लाख रुपये तक सीड फंड सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ युवाओं को तकनीक, नवाचार, कौशल और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने से न केवल नए व्यवसाय खड़े होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी निर्मित होंगे। मुख्यमंत्री साय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि प्रदेश में 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके साथ ही नागरिकों को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी।

नई औद्योगिक नीति के बाद 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ईज ऑफडूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों के माध्यम से निवेश प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 450 से अधिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। इन सुधारों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है और नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता- मंत्री टंक राम वर्मा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के प्रयास अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर मंत्री वर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की।

मुलाकात के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री वर्मा ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में केंद्रीय विद्यालय की महत्ता और स्थानीय विद्यार्थियों के हित से जुड़े विभिन्न पहलुओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने प्रक्रिया को गति देते हुए जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आश्वस्त किया कि इस विषय पर जल्द ही आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के इस आश्वासन से जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर बेहद सकारात्मक चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी जी द्वारा जल्द निर्णय लेने का आश्वासन मिलना पूरे जिले के लिए सुखद और उत्साहजनक है।

शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास: उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ी यह पहल जिले के समग्र शैक्षणिक विकास को एक नई गति प्रदान करेगी।

विद्यार्थियों को मिलेंगे बेहतर शैक्षणिक अवसर

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना लंबे समय से क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रही है। वर्तमान में बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को बड़े शहरों या अन्य जिलों का रुख करना पड़ता है। जिले में विद्यालय खुलने से स्थानीय विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक माहौल उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय के संचालन के लिए शुरुआती दौर में अस्थायी भवन की व्यवस्था के साथ-साथ भविष्य में स्थायी भवन निर्माण हेतु भूमि चिह्नित एवं आरक्षित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

'पावस प्रसंग' में शास्त्रीय नृत्य-संगीत से सजी सांस्कृतिक संध्या

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभागीय आयोजन-2026 के अंतर्गत राजधानी रायपुर में 'पावस प्रसंग' का आयोजन किया गया। महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में वर्षा ऋतु की भावभूमि को शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया गया। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, भरतनाट्यम और कथक समूह की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भारतीय शास्त्रीय कला की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराया।

'पावस प्रसंग' के प्रथम दिवस की पहली प्रस्तुति सुश्री अलका कुर्रे ने शास्त्रीय गायन के माध्यम से दी। कक्षा आठवीं की विद्यार्थी सुश्री अलका कुर्रे ने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम की सांगीतिक शुरुआत की। उनकी प्रस्तुति में शास्त्रीय संगीत की सुरमयी एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति देखने को मिली।

इसके बाद होरित गौर ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में शास्त्रीय नृत्य की लय, भाव और सौंदर्य को प्रभावी ढंग से सामने रखा। भरतनाट्यम की मुद्राओं और भावाभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण डॉ. आरती सिंह एवं उनके 10 विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कथक रहा। प्रस्तुति में 'शिव पंचाक्षर स्तोत्र' सहित वर्षा ऋतु की भावभूमि को कथक की लय, ताल, मुद्राओं और भावाभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

कोरिया में 174 किसानों को मिला 1020 बैग उन्नत मत्स्य बीज

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तथा महिला स्व-सहायता समूहों की आय बढ़ाने की दिशा में कोरिया जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के प्रयासों से वीबी-ग्राम-जी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) एवं मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले के 174 किसानों को 1020 बैग उन्नत मत्स्य बीज वितरित किए गए।

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बिहान महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को 'आजीविका डबरी योजना' से जोड़ा गया है। योजना के तहत निर्मित डबरियों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देश पर मत्स्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को अनुदान आधारित मत्स्य बीज उपलब्ध कराया गया। कुल 174 हितग्राहियों में 68 आजीविका डबरी हितग्राही तथा 106 अन्य किसान शामिल हैं। अन्य हितग्राहियों के पास तालाब, अमृत सरोवर अथवा व्यक्तिगत डबरी उपलब्ध है। मत्स्य पालन से इन्हें कृषि के साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।

क्षेत्रवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता: मंत्री राजेश अग्रवाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज लखनपुर स्थित अपने निज निवास पर क्षेत्र से पहुंचे सम्मानित नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं और स्थानीय विषयों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं मांगों के त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी ली और प्रत्येक विषय को प्राथमिकता के साथ समझा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। पात्र लोगों को शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ समय पर मिले और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता है। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता से सीधा संवाद उनकी जिम्मेदारी भी है और जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम भी। क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को लेकर सहजता से संपर्क कर सके तथा उनकी बात संबंधित स्तर तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निराकरण करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

टाउन हॉल की छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ समापन इतिहास से विकास तक की यात्रा ने किया प्रभावित

स्वतंत्रता संग्राम, 'वंदे मातरम' की गौरवगाथा और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा रही मुख्य आकर्षण का केंद्र

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। 15 से 21 अगस्त तक आयोजित इस प्रदर्शनी को नागरिकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम, वीर सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से लेकर 'वंदे मातरम' की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा तथा राज्य की विकास और सुशासन यात्रा को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया।

इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े दुर्लभ छायाचित्र, ऐतिहासिक दस्तावेज और महत्वपूर्ण प्रसंग प्रदर्शित किए गए। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रदेश के योगदान और वीर सेनानियों के संघर्ष को तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने इन छायाचित्रों को उत्सुकता से देखा और कहा कि पुस्तकों में पढ़े इतिहास को तस्वीरों के माध्यम से देखना उनके लिए प्रेरणादायी अनुभव रहा।

प्रदर्शनी में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' की 150 वर्षों की यात्रा पर विशेष खंड बनाया गया था। इसमें इसके ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभावना जागृत करने में इसकी भूमिका को प्रदर्शित किया गया। इस खंड को विद्यार्थियों और युवाओं ने विशेष रुचि के साथ देखा।

प्रदर्शनी में एआई तकनीक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की पृष्ठभूमि के साथ डिजिटल तस्वीर तैयार करने की सुविधा ने बच्चों और युवाओं को खासा आकर्षित किया। आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत से जुड़ने का यह अनुभव आगंतुकों के लिए नया और रोचक रहा।

इस प्रदर्शनी में राज्य की विकास यात्रा को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में आए बदलावों को तस्वीरों और सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

महिलाओं, किसानों, युवाओं, श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों के सशक्तिकरण से जुड़ी उपलब्धियों के साथ सुशासन तिहार, हरित छत्तीसगढ़, सड़क एवं रेल संपर्क, अधोसंरचना विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों की झलक भी प्रदर्शनी में देखने को मिली।

वृत्तचित्र के माध्यम से दिखाई विकास की यात्रा प्रदर्शनी परिसर में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया गया। इससे आगंतुकों को राज्य में हुए विकास कार्यों और योजनाओं के प्रभाव को दृश्यों के माध्यम से समझने का अवसर मिला। आज सेजस शहीद स्मारक स्कूल फफाडीह 54 छात्र-छात्राओं ने अवलोकन किया। ऐश्वर्य यादव, दिव्यांशु आदिल,अवंतिका सिंह नैंसी साहू और टीना जंघेल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके लिए यह बड़ा ही रोचक और अनोखा अनुभव रहा है जो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा।

क्विज से परखा छत्तीसगढ़ का ज्ञान

इस प्रदर्शनी परिसर में छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, पर्यटन और महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित क्विज भी आयोजित की गई। विद्यार्थियों और युवाओं ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। क्विज के माध्यम से मनोरंजन के साथ लोगों को अपने राज्य के बारे में अधिक जानने और अपने ज्ञान को परखने का अवसर मिला।

सेवा सेतु से सेवा हुई सरल, समय पर मिले दस्तावेजों से आसान हुआ श्रद्धा का उच्च शिक्षा का सफर

रायपुर। नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में सेवा सेतु पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध होने से आम नागरिकों के साथ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिल रही है। दुर्ग जिले के भिलाई निवासी श्रद्धा कुमारी रामटेके के लिए सेवा सेतु की सुविधा उनकी उच्च शिक्षा की राह में आई महत्वपूर्ण अड़चन को दूर करने का माध्यम बनी। श्रद्धा कुमारी रामटेके के आधार कार्ड में उनका नाम गलत दर्ज था। नाम में संशोधन के लिए गजट प्रकाशन आवश्यक था।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

तालाब में डूबने से दो भाइयों की मौत

बिलासपुर। बिलासपुर में गुरुवार शाम तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भक्त प्रहलाद गुरुवार शाम वह अपने दो बेटों दीपू पैकरा (7) और चींटू पैकरा (4) को लेकर तालाब के पास गए थे। बच्चों को तालाब किनारे छोड़कर वह कुछ दूर चले गए और मोबाइल पर बात करने लगे। इसी दौरान तालाब किनारे खेल रहा 4 वर्षीय चींटू अचानक पानी में फिसल गया। वह गहरे पानी में जाकर डूबने लगा। छोटे भाई को डूबता देखकर सात वर्षीय दीपू उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गया। गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वह भी पानी में डूब गया। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में उतरकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मोबाइल स्क्रेचिंग करने वाले नाबालिग समेत दो आरोपी पकड़ाए

रायपुर। राजधानी रायपुर में चोरी की एक्टिवा से मोबाइल स्क्रेचिंग करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पूछताछ में एक आरोपी की पहचान वरुण साहू (23 वर्ष) के रूप में हुई, जबकि दूसरा आरोपी विधि के साथ संघर्षरत बालक निकला। पूछताछ में दोनों ने एक्टिवा चोरी करने और इसी वाहन से मोबाइल स्क्रेचिंग की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। दोनों के कब्जे से चोरी की एक्टिवा और स्क्रेचिंग किए गए 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की एक्टिवा के साथ 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अब आरोपियों से जुड़ी अन्य तीन मोबाइल चोरी की घटनाओं की भी जांच कर रही है।

वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुत्र गिरफ्तार

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सनसनीखेज माता-पिता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सपड़ा के परसापारा में 55 वर्षीय हीराधर यादव और उनकी 50 वर्षीय पत्नी गुलाबी यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके बड़े बेटे जदू यादव (34) को गिरफ्तार किया है। मृतक दंपती का बड़ा बेटा जदू यादव फरार था, जिसके चलते पुलिस का शक उस पर गहरा गया। आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते टांगी से हमला कर माता-पिता की हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस मामले में हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

सीएम पोर्टल की शिकायत पर निगम की कार्रवाई, शासकीय स्कूल की बाउंड्रीवाल से हटाया अवैध कब्जा

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नागरिकों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर निगम की टीम ने शुक्रवार को जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कार्रवाई की। टीम ने शासकीय स्कूल की बाउंड्रीवाल से लगे कब्जे को तोड़ दिया।

शिकायत में शासकीय स्कूल की बाउंड्रीवाल से लगे हुए स्थान पर अवैध कब्जे की जानकारी दी गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निगम के संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया। जांच के बाद शासकीय स्कूल की बाउंड्रीवाल से लगे अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम अधिकारियों ने कहा कि शासकीय भूमि, सार्वजनिक स्थानों एवं सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक एवं शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा न करें।

इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीव शिकार पर बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार

मुखबिर की सूचना पर नीतिकाकलेर क्षेत्र में कार्रवाई, शिकार सामग्री और वन्यप्राणी का मांस बरामद

श्रीकंचनपथ समाचार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों की सुरक्षा और अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर में वन विभाग की टीम ने वन्यजीव शिकार के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान वन्यप्राणी का मांस, संभावित रूप से नीलगाय का मांस, तथा शिकार में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर कार्रवाई जारी है।

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर परिक्षेत्र पासेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम नीतिकाकलेर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने 19 अगस्त 2026 को मौके पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

बारिश के बीच भी वन अमले की लगातार गश्त

वन विभाग के अनुसार यह कार्रवाई अधिकारियों के मार्गदर्शन, मजबूत सूचना तंत्र और मैदानी अमले की सतत निगरानी का परिणाम है। मानसून के दौरान लगातार बारिश, नदी-नालों में बढ़े जलस्तर और कठिन आवागमन के बावजूद वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त कर वन्यजीवों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी

इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में वन अपराध और अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही वन अमले को लगातार सक्रिय रखा गया है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

वन्यजीव संरक्षण में ग्रामीणों की भागीदारी जरूरी

वन विभाग ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वन अपराध, अवैध शिकार या वन्यजीवों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल निकटतम वन विभाग कार्यालय को दें। विभाग ने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और स्थानीय लोगों की सहभागिता से वन संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत बनाया जा सकता है। इस कार्रवाई में अधीक्षक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर, परिक्षेत्र अधिकारी फरसेगढ़/पासेवाड़ा, सेण्ड्रा, कुटरू बफर, कुटरू कोर एवं मद्देड़ बफर सहित इन्द्रावती टाइगर रिजर्व का मैदानी अमला सक्रिय रूप से शामिल रहा।

मवेशी को बचाने के लिए मोड़ी बस, पेड़ से टकराई, 15 से अधिक यात्री घायल

श्रीकंचनपथ समाचार

जशपुरनगर। सन्ना थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर गुरगुरी से बगीचा जा रही ग्रामीण बस सेवा की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गुरगुरी-बेडेकोना पुल से आगे हल्के मोड़ के पास बस सड़क किनारे स्थित सरई के पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 15 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इनमें करीब चार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घायलों को आसपास के ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश की स्थिति सामान्य बताई गई। हादसा गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे रपटा नाला जैसे क्षेत्र के पास हुआ। बस गुरगुरी से यात्रियों को लेकर बगीचा की ओर जा रही थी।

हादसे के समय बस में 15 से अधिक यात्री सवार थे। गुरुवार को चंपा में साप्ताहिक बाजार का दिन होने के कारण बस में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ होने की बात सामने आई है। बाजार जाने और वहां से लौटने वाले ग्रामीण भी बड़ी संख्या में बस में सवार थे। प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक बस गुरगुरी-बेडेकोना पुल पार करने के बाद हल्के मोड़ की ओर बढ़ रही थी।

इसी दौरान चालक के सामने मवेशी आने की बात सामने आई। उसे बचाने के प्रयास में बस को मोड़ने के दौरान चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बस सड़क से उतरकर किनारे स्थित सरई के पेड़ से जा भिड़ी।

घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल हादसे में एकम्बा निवासी सुधू (50 वर्ष) को चोटें आई हैं। वहीं बस में सवार 75 वर्षीय एलेकजेंडर तिर्की भी घायल हुए हैं। उनके हाथ और पैर में गंभीर चोट लगी है। उपचार के दौरान उनके चोट वाले स्थान पर तीन टांके लगाए गए। फिर उन्हें जिला अस्पताल रिफर किया गया। उपचार के बाद सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वर्तमान में सभी स्वस्थ हैं।

महिलाओं के नाम पर मुद्रा व पर्सनल लोन लेकर रकम हड़पी, आरोपिया गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में स्व सहायता समूह में निवेश कराने के बाद महिला सदस्यों के नाम पर लोन निकलवाकर रकम हड़पने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपिया द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच देकर मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाए गए। लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग करने तथा हितग्राहियों के बैंक दस्तावेज अपने पास रख लिए। इस मामले में महिला सदस्यों की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया।

इस मामले में त्रिवेणी साहू, निवासी कुरूद द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच दिया गया। आरोपिया द्वारा महिलाओं से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाकर लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग किया गया। हितग्राहियों के एटीएम कार्ड एवं बैंक पासबुक अपने पास रख लिए। विद्या साहू ने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी महिला सदस्यों से की गई।

शिकायत पर थाना जामुल में धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए को आरोपिया हिरासत में लिया गया। पूछताछ एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपिया द्वारा महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम स्वयं प्राप्त कर खर्च करना बताया गया। आरोपिया के कब्जे से संबंधित दस्तावेज एवं कार्ड जब्त किए गए। उक्त कार्यवाही में थाना जामुल में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण की विवेचना में शिकायत के तथ्यों का परीक्षण, आरोपिया की पतासाजी, घेराबंदी एवं आवश्यक दस्तावेजों की जप्ती की कार्रवाई की गई।

मकान के बेसमेंट से बिना लाइसेंस कीटनाशक-खाद जब्त

बिना दस्तावेज किया जा रहा था स्टॉक, एक्सपायर-डुप्लीकेट दवाएं मिलीं

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक मकान के बेसमेंट से बड़ी मात्रा में कीटनाशक और कृषि में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां मिली हैं। कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पता चला कि बिना लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों के कृषि दवाइयों और खाद का भंडारण किया गया था। आशंका है कि ये कीटनाशक और कृषि दवाइयां गाजियाबाद से अवैध तरीके से मंगाई गई थीं। इन्हें यहां लाकर बेचने की तैयारी की जा रही थी।

कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि लोखंडी में एक मकान के बेसमेंट में बड़ी मात्रा में कीटनाशक और कृषि दवाइयां रखी गई हैं। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान बेसमेंट में काफी मात्रा में कृषि दवाइयां मिलीं। इन दवाइयों को रखने के लिए जरूरी लाइसेंस और दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कीटनाशक और उर्वरक जब्त कर लिए।

टीम अब जब्त की गई दवाइयों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने प्रत्येक दवा की कंपनी का नाम, बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट समेत अन्य जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान मिली कुछ दवाओं के एक्सपायर और नकली होने की आशंका है। हालांकि, अभी यह साफनहीं है कि दवाएं वास्तव में एक्सपायर या नकली हैं। इसकी पुष्टि जांच और सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। अगर जांच में दवाएं नकली या गुणवत्ता में खराब पाई जाती हैं, तो मामला और गंभीर हो सकता है। कृषि दवाओं को रखने और बेचने के लिए तय नियम हैं। ऐसे में बेसमेंट में इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं मिलने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। कृषि विभाग जरूरी लाइसेंस, अनुमति और दस्तावेजों की जांच कर रहा है।

बरामद दवाओं की पूरी मात्रा और अन्य जानकारी सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

एसएसपी ने दिखाई गंभीरता, पुलिस टीम भेजा

कृषि विभाग से मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने सकरी थाने की पुलिस टीम को मौके पर भेजा। कृषि अधिकारियों के अनुसार बरामद सामग्री टनों में है, जिसकी गिनती और तौल कर लिस्टिंग चल रही है।

आरक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग के उतई थाना क्षेत्र में पुलिस आरक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ग्राम सेलूद निवासी गैंदलाल बंछोर ने 20 अगस्त 2026 को थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि ग्राम अतरिया, जिला बेमेतरा निवासी उमेश दास मानिकपुरी ने उनके बेटे विकास बंछोर को पुलिस आरक्षक के पद पर भर्ती कराने का भरोसा दिया था। नौकरी लगवाने की बात कहकर उससे कुल 12 लाख रुपए लिए गए। परिवार को उम्मीद थी कि रकम देने के बाद बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन समय बीतने के बाद भी भर्ती नहीं हुई। जब परिवार ने अपनी रकम वापस मांगी तो कथित तौर पर पैसे वापस नहीं किए गए। इसके बाद प्रार्थी ने पुलिस से शिकायत की।

2023 में लिए पैसे, तीन साल बाद पहुंची शिकायत पीड़ित से रकम वर्ष 2023 में ली गई थी, जबकि पुलिस में शिकायत 20 अगस्त 2026 को दर्ज कराई गई। यानी करीब तीन साल तक नौकरी लगने या रकम वापस मिलने का इंतजार चलता रहा। शिकायत मिलने के बाद उतई पुलिस ने लेन-देन और आरोपों से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उमेश दास मानिकपुरी और बिलासपुर निवासी राजेश वर्मा को गिरफ्तार किया।

बैंक खाते और मोबाइल जब्त पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के साथ ही मामले से जुड़े बैंक खाते और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सरकारी विभाग में आरक्षक की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर युवक के परिवार से पैसे लिए। नौकरी नहीं लगी और रकम भी वापस नहीं की गई। इसी आधार पर मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल उतई पुलिस मामले में पैसों के लेन-देन और आरोपियों की भूमिका से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

रायपुर में करंट से मां-बेटे की मौत, कपड़े लेने गई थी, बचाने पहुंचा बेटा भी चपेट में आया

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रायपुर में करंट लगने से मां-बेटे की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब मां बालकनी में सूख रहे कपड़े लेने गई थी। कपड़े उतारने के दौरान जैसे ही उन्होंने जीआई पाइप को छुआ, वह करंट की चपेट में आ गईं।

मां को करंट से चिपका देख उनका बेटा उन्हें बचाने पहुंचा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मां अपने बेटे के साथ बेटी से मिलने रायपुर आई थीं। उनकी बेटी किराए के मकान में रहती है। शुरुआती जांच में पता चला कि करंट कूलर से जीआई पाइप में फैला था। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की है।

मृतकों की पहचान कल्याणी यादव (54) और उनके बेटे मधुसूदन यादव (23) के रूप में हुई है। जो कि धरसींवा क्षेत्र के कूंरा गांव के रहने वाले थे। परिवार खेती-किसानी से जुड़ा है। कल्याणी अपने बेटे के साथ रायपुर में रह रही बेटी से मिलने आई थीं। उनकी बेटी छत्तीसगढ़ नगर में किराए के मकान में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है।

शुक्रवार दोपहर कल्याणी कपड़े लेने बालकनी में पहुंचीं। जैसे ही उन्होंने पाइप को छुआ, उन्हें तेज करंट लगा और वह पाइप से चिपक गईं। मां को बचाने के लिए मधुसूदन तुरंत उनकी ओर दौड़ा। उसने जैसे ही उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, वह भी करंट की चपेट में आ गया।

कूलर से जीआई पाइप और बालकनी की रेलिंग में फैला करंट

हादसे की जानकारी मिलते ही टिकरापारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मुआयना किया। इसके बाद दोनों शवों का पंचनामा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस का कहना है कि मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच की जा रही है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि मकान की बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए विंडो कूलर और रेलिंग के बीच जीआई पाइप लगाया गया था। इसी पाइप पर कपड़े सुखाए जा रहे थे। आशंका है कि कूलर में करंट आने के बाद बिजली का प्रवाह जीआई पाइप और बालकनी की रेलिंग तक पहुंच गया।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग
-:: व्यक्तिगत सूचना ::-

(रा0प्र0क0/-202608101000024/अ-6/वर्ष 2025-26)
प्रति,
अवधराम पिता भोला
निवासी- वार्ड नं. 04, ए.सी.सी.जामुल भिलाई
पक्षकार - श्रीमती ए. निर्मला पति ए. मरिया दास
निवासी - क्वा., नं. 07, इंदिरा पैलेष सेक्टर 15 भिलाई
विरूद्ध
अनावेदक- छ.ग. शासन
आपको सूचित किया जाता है इस न्यायालय का रा.प्र.के. 202608101000024/अ-6/वर्ष 2025-26 आवेदिका श्रीमती ए. निर्मला पति श्री ए. मरिया दास निवासी क्वा. नं. 07, इंदिरा पैलेष सेक्टर 15 भिलाई द्वारा ग्राम-कुरूद प.ह.नं. 46 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 944/1 का दु. रकबा 0.015 है/1645 वर्गफीट भूमि को रजिस्ट्री बैनामा के माध्यम से दिनांक 24.06.2017 को विक्रेता अवध राम आ. स्व. भोला निवासी-लीला मंच के पास कुरूद भिलाई से क्रय किया गया है, कि रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अत: उपरोक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 25/08/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज 20/08/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

कोरबा में नशे में तेज रफ्तार कार ने 4 मवेशियों को कुचला

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां गुरुवार देर रात नशे में धुत्त तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क पर मौजूद चार मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीन मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मवेशी घायल हो गया। यह घटना उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा पॉवर जनरेट ऑफिस के सामने की बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थिति विवाद तक पहुंच गई, जिसके बाद 112 को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नशे में वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।

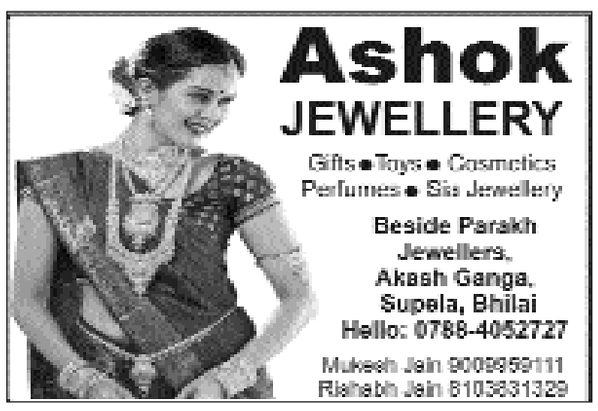

खास खबर

राखी से पहले मिली महतारी वंदन की 30वीं किस्त

एमसीबी। रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त हितग्राहियों के खातों में पहुंचने से लाखों परिवारों में त्योहार की खुशियां और बढ़ गई हैं। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम हर्रा की रहने वाली नंदिनी राय भी ऐसी ही लाभार्थी हैं, जिनके लिए इस बार महतारी वंदन योजना की राशि राखी का सबसे बड़ा उपहार बनकर आई है। नंदिनी ने कहा, 'विष्णु भैया ने राखी से पहले ही हमारी खुशियां बढ़ा दीं। यह राशि त्योहार के साथ-साथ बच्चों और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में भी बहुत काम आती है।'

सागरपुर की रीना ने भी जताया विष्णु भैया के प्रति आभार

रायपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले योजना की 1000 रुपये की मासिक सहायता राशि हितग्राहियों के खातों में पहुंचने से महिलाओं की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। कोरिया जिले के सागरपुर की रहने वाली श्रीमती रीना साहू भी उन महिलाओं में शामिल हैं, जिनके लिए यह राशि इस बार राखी के त्योहार का विशेष उपहार बनकर आई है। श्रीमती रीना साहू के खाते में राखी से पहले महतारी वंदन योजना की 1000 रुपये की राशि पहुंची। सहायता राशि मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भावुक शब्दों में कहा, 'हमारे विष्णु भैया ने हमें राखी का तोहफा पहले ही दे दिया। महतारी वंदन योजना के एक हजार रुपये समय पर मिल जाने से हमारे त्योहार की खुशियां और बढ़ गई हैं।'

रमदहा वॉटरफॉल में लगे सोलर हाई मास्ट : पर्यटकों के साथ ही ग्रामीणों का जीवन भी हुआ आसान

श्रीकंचनपथ समाचार

एमसीबी। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बेनीपुरा स्थित रमदहा वॉटरफॉल में 2 सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनकी स्थापना डीएमएफ मद से 10 लाख 76 हजार रुपये की लागत से की गई है। इन संयंत्रों के शुरू होने से पर्यटन क्षेत्र में रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हुई है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा के साथ सुरक्षा भी मिली है।

जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित रमदहा वॉटरफॉल प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और जलप्रपात के कारण जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। सुदूर वनांचल में स्थित होने के कारण यहां पहले पारंपरिक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सूर्यास्त के बाद पर्यटन स्थल और आसपास का क्षेत्र अंधकारमय हो जाता था, जिससे रात्रिकालीन आवागमन में लोगों को कठिनाई होती थी।

रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था से पर्यटन स्थल पर आने-जाने वाले लोगों को रास्ते और आसपास का क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देने लगा है। वन क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों की मौजूदगी को देखते हुए प्रकाश व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे अंधेरे के कारण होने वाली परेशानियों और जोखिमों को कम करने में मदद मिल रही है।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले शाम होते ही क्षेत्र में अंधेरा छा जाता था, लेकिन अब सोलर हाई मास्ट की रोशनी से आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। पर्यटकों को भी बेहतर वातावरण मिल रहा है।

रमदहा वॉटरफॉल में सोलर हाईमास्ट की स्थापना दूरस्थ वनांचल में स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास का उदाहरण है। इससे पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यटन स्थल की उपयोगिता भी बढ़ी है। रमदहा वॉटरफॉल में सुविधाओं के विस्तार से पर्यटकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हुआ है।

पर्यावरण को लेकर शासन सख्त : केवल पौधे लगा देने से नहीं हो सकता वनों का पुनरुद्धार

खनन प्रभावित वन भूमि के पुनरुद्धार में वैज्ञानिक वानिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता : केदार कश्यप

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। खनन समाप्त होने के बाद केवल पौधे लगा देना ही वन भूमि का पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि उसे वैज्ञानिक तरीके से पुनर्स्थापित कर पुन: एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करना आवश्यक है। खनिज संसाधनों के उपयोग के बाद वन भूमि को उसकी प्राकृतिक पहचान लौटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।

छत्तीसगढ़ शासन के वन व जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कोरबा प्रवास के दौरान एनटीपीसी के प्रशासनिक भवन में सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों के प्रतिनिधियों तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम के प्रावधानों और स्वीकृत शर्तों के अनुरूप खनन एवं परियोजनाओं से प्रभावित वन भूमि के पुनरुद्धार के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (लैंड मैनेजमेंट) सुनील मिश्रा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, हिंडालको, एसईसीएल, एनटीपीसी, बालको, अडानी सहित प्रमुख सार्वजनिक व निजी औद्योगिक एवं खनन उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी तथा वन विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

वन मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलना चाहिए। विकास के लिए संसाधनों का उपयोग आवश्यक है, लेकिन इसके साथ प्रकृति को हुई क्षति की भरपाई और वन भूमि को पुन: स्वस्थ स्वरूप प्रदान करना भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी तकनीकी एवं व्यावहारिक दिशा-निर्देशों को सभी संबंधित कंपनियों एवं अधिकारियों को इनका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री कश्यप ने कहा कि वन भूमि केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि जैव विविधता, वन्यजीवों, जल स्रोतों और स्थानीय समुदायों के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों के बाद इसके पुनरुद्धार में दीर्घकालिक पर्यावरणीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

वन मंत्री ने सभी औद्योगिक एवं खनन कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद का प्रभावी और संवेदनशील उपयोग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों एवं स्थानीय समुदायों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उन्नयन के लिए सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में ठोस और सकारात्मक बदलाव लाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि विकास का लाभ प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों तक भी प्रभावी रूप से पहुंचे।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका पुनरुद्धार किसी औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। रेस्टोरेशन एवं रिक्लेमेशन के प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिक वानिकी सिद्धांतों, स्थानीय पारिस्थितिकी और स्थल की प्राकृतिक विशेषताओं को केंद्र में रखा जाए। संबंधित कंपनियों को निर्देशित किया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में केवल तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों का एकरूप पौधरोपण करने के बजाय स्थानीय एवं देशज प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। प्रजातियों का चयन क्षेत्र की जलवायु, मृदा, स्थल-गुण, जल उपलब्धता और स्थानीय वन संरचना के अनुरूप किया जाए, जिससे लगाए गए पौधे दीर्घकाल में स्थायी वन के रूप में विकसित हो सकें और प्राकृतिक पुनरुत्पादन को भी बढ़ावा मिले।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री पांडे ने निर्देशित किया कि वैज्ञानिक पुनरुद्धार का दायरा केवल ओवरबर्डन डंप तक सीमित न रखा जाए। खनन के दौरान खोदे गए एवं प्रभावित संपूर्ण क्षेत्र में भूमि सुधार, मृदा संरक्षण और पौधरोपण का कार्य वैज्ञानिक सिल्वीकल्चरल तकनीकों के अनुसार किया जाए। उन्होंने मृदा की स्थिरता बनाए रखने, भू-क्षरण रोकने तथा खनन के बाद भूमि को पुन: वन विकास के लिए सक्षम बनाने के लिए स्थल-विशिष्ट तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया।

महिला बाल विकास मंत्री ने दिव्यांगों को दिए सहायक उपकरण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 6 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण एवं सामग्री वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा उनके स्वास्थ्य, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और सामने आ रही कठिनाइयों के संबंध में जानकारी ली।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने सौनी निवासी धनेश्वर सोनी को बैसाखी, भनौरा निवासी निशांत पैकरा एवं बड़की महरी निवासी महिमा दास को व्हीलचेयर, भनौरा निवासी गौरीशंकर एवं फनु सिंह को स्टिक तथा सौनी निवासी ममता पाल को स्मार्टफोन प्रदान किया। सहायक उपकरण प्राप्त होने पर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन के प्रति आभार जताया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि जरूरतमंद दिव्यांगजनों तक शासन की योजनाओं और सहायक उपकरणों का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

आईजीकेवी पेपर लीक : परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो कठोर कार्रवाई होगी - मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी (कीट विज्ञान) विषय की परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने या विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। साथ ही तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तकनीकी जांच में साइबर सेल की भी सहायता ली जा रही है, ताकि

प्रश्नपत्र के प्रसारण की पूरी कड़ी का पता लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भर्ती हो या शैक्षणिक परीक्षा, उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, उनका विश्वास और उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। इस मामले की पूरी तह तक जाकर जांच की जाएगी। प्रश्नपत्र कहां से बाहर आया, किसने इसे प्रसारित किया और इसमें किन लोगों की भूमिका रही, प्रत्येक तथ्य सामने लाया जाएगा। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

आईजीकेवी की बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा में 27 कृषि महाविद्यालयों के लगभग 1,200 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित होने की शिकायत सामने आई थी। निरस्त परीक्षा सितंबर के प्रथम सप्ताह में पुन: आयोजित की जाएगी।

गठित जांच समिति द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रश्नपत्र और परीक्षा में उपयोग किए गए मूल प्रश्नपत्र का मिलान करने के साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि प्रश्नपत्र सबसे पहले किस स्रोत से बाहर आया, किन माध्यमों से आगे प्रसारित हुआ और इसकी पहुंच कहां तक रही।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में रखा दो साल की उपलब्धियों का लेखाजोखा

453 शिक्षक विहीन स्कूलों को मिले शिक्षक, 7000 का प्रमोशन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग की विगत दो वर्षों की उपलब्धियों पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संयुक्त पत्रकारवार्ता ली। विभाग द्वारा गुणवत्ता सुधार, शिक्षकों की उपलब्धता एवं पदोन्नति, भर्ती प्रक्रिया, विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं, विद्यालय अधोसंरचना, बहुभाषी शिक्षा तथा तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

श्री यादव ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अनुरूप 10,538 विद्यालयों का समायोजन किया गया। 15,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया। 453 शिक्षकविहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति तथा 4,729 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। टी संवर्ग में 1,335 तथा ई संवर्ग में 1,478, कुल 2,813 पदों पर प्राचार्यों की पदोन्नति की गई। टी संवर्ग में 1,798 व्याख्याताओं की पदोन्नति तथा विगत दो वर्षों में विभिन्न पदों पर 7,000 से अधिक पदोन्नतियां की गई हैं।

श्री यादव ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के 848 पद स्वीकृत किए गए। विगत दो वर्षों में 2,104 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त 5,000 शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में है। स्वामी आत्मानंद एवं विवेकानंद विद्यालयों में 3,000 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।

मंत्री ने बताया कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में संविदा पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की शुरुआत की गई है।

15 जुलाई 2024 से विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई। कक्षा 1 एवं 2 की हिंदी पुस्तकों में बारहखड़ी को शामिल किया गया। 16 स्थानीय तथा 4 अंतरराज्यीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों तैयार किये गये हैं। कक्षा 1, 2, 3 एवं 6 के विषयों की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों का अनुकूलन किया गया है। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सहायक वाचन सामग्री भी विकसित की गई है।

श्री यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाषा-चित्रण करने वाला देश का पहला राज्य है। बस्तर संभाग में बच्चों की भाषा के कक्षा में उपयोग के लिए 2,700 तथा सरगुजा संभाग में 2,368 शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है। कक्षा 1 से 3 तक छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी और सादरी में पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

शिक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक एवं टीके एप्प व्यवस्था लागू की गई है। 85 प्रतिशत शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो रही है।

कक्षा 1 से 10 तक के 45,33,261 विद्यार्थियों को सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पाठ्यपुस्तक मिल गए। हिंदी-अंग्रेजी के अतिरिक्त 16 बोलियों में पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की पहल की गई। 1,62,827 बालिकाएं सरस्वती सायकल योजना से लाभान्वित हुईं। 28,63,786 बच्चों को गणवेश प्रदान किया गया।

परीक्षा परिणामों में सुधार

शिक्षामंत्री श्री यादव ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणामों में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

श्री यादव ने कहा कि प्रत्येक शनिवार विद्यार्थियों के लिए तनाव एवं भयमुक्त वातावरण में पठन-पाठन के साथ खेल, योग एवं व्यायाम, स्थानीय कला-संस्कृति, महापुरुषों की जयंती, तीज-त्योहार एवं ऐतिहासिक तिथियों से परिचित कराने वाली गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

शिक्षामंत्री ने बताया कि विगत तीन वर्षों में 504 नवीन विद्यालयों की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 700 भवनविहीन विद्यालयों के लिए नवीन विद्यालयों का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023 से 2026 के मध्य 2,583 नवीन अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति दी गई।

मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

जैव ऊर्जा से और मजबूत होगी छत्तीसगढ़ की ऊर्जा सुरक्षा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि अवशेष, वन संसाधन, पशुधन अपशिष्ट और नगरीय जैव अपशिष्ट को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। कम्प्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोएथेनॉल और अन्य जैव ईंधनों के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का योजनाबद्ध उपयोग छत्तीसगढ़ को देश की उभरती जैव ऊर्जा अर्थव्यवस्था में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है।

इन्हीं संभावनाओं और भावी कार्ययोजना पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, इसके टेक्निकल पार्टनर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर के सभागार में ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास में जैव ऊर्जा की भूमिका पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित की गई।

विशेषज्ञों ने कहा कि राज्य में उपलब्ध बायोमास संसाधनों की मजबूत वैल्यू चेन विकसित कर उन्हें स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने के साथ उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को गति मिलेगी।

कार्यशाला में बताया गया कि राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 लागू की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में बायोएनर्जी परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों और सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जैव ऊर्जा का विस्तार केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इससे कृषि अवशेषों और अपशिष्ट का आर्थिक उपयोग संभव होगा, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार होंगे और सर्कुलर इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा तथा सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लक्ष्यों को एक साथ हासिल किया जा सकता है। बायोमास को केवल कृषि अवशेष अथवा अपशिष्ट के रूप में देखने के बजाय ऊर्जा आधारित आर्थिक विकास और हरित रोजगार के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित करना होगा।

उन्होंने कहा कि कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायोएथेनॉल और अन्य बायोफ्यूल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनके उपयोग से उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ संसाधनों के पुन: उपयोग पर आधारित सर्कुलर इकोनॉमी को भी मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि और वन आधारित अर्थव्यवस्था जैव ऊर्जा के विकास के लिए अनुकूल आधार उपलब्ध कराती है। उपलब्ध संसाधनों को तकनीक, निवेश और प्रभावी बाजार व्यवस्था से जोड़कर प्रदेश में जैव ऊर्जा आधारित नए आर्थिक अवसर तैयार किए जा सकते हैं।

सुकमा के 39 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों में स्थापित किए माइक्रो एटीएम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच के अनुरूप शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में सुकमा जिले में ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा उनके गांव में ही उपलब्ध कराने की पहल की गई है। कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन में जिले के 39 अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए गए हैं।

जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने शुक्रवार को ग्राम स्तरीय उद्यमियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए। इस सुविधा के शुरू होने से अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए दूर स्थित बैंक शाखाओं तक जाने की जरूरत नहीं होगी।

माइक्रो एटीएम के माध्यम से किसान और ग्रामीण अपने गांव के अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पर ही एटीएम कार्ड से आसानी से राशि निकाल सकेंगे। धान बिक्री की सहित अन्य शासकीय योजनाओं की राशि की निकासी भी गांव में ही की जा सकेगी।

इससे ग्रामीणों का समय और आने-जाने का खर्च बचेगा। खासकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित होगी। ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बैंक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। यह पहल गांवों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीणों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करेगी।

ऐसे हितग्राही, जिनका आधार आधारित भुगतान सिस्टम सक्रिय नहीं है, वे भी माइक्रो एटीएम के माध्यम से आवश्यक राशि निकाल सकेंगे। इससे बैंकिंग सेवाओं की पहुंच अधिक लोगों तक सुनिश्चित होगी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950